mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-02 अंक-218 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़
08 अगस्त 2026 शनिवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

: ब्रीफ बॉस :

आतंकी पन्नू का दावा- जालंधर के स्कूल में फहराया खालिस्तानी

झंडा

जालंधर,एजेंसी। जालंधर के शाहकोट इलाके के तहत आने वाले सरकारी मिडिल स्कूल कोटला हेरां में दीवार और प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर खालिस्तानी झंडा फहराने का दावा किया गया है। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो में यह दावा किया।

पन्नू ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया गया हो, उन पर जबरन स्वतंत्रता का जश्न नहीं थोपा जा सकता। स्वच्छ ने घटना का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मामले में एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं 15 अगस्त से ठीक पहले हुई इस घटना के बाद सुरक्षा

थाईलैंड में 9वीं के छात्र ने स्कूल में फायरिंग की,6 की मौत

बैंकॉक,एजेंसी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास एक हाई स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र ने शुक्रवार को अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में 3 टीचर और 3 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें दो की हालत गंभीर है।

पुलिस के मुताबिक, घटना नोंथाबुरी प्रांत के डेबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल की है। जांच में पता चला कि स्कूल जाने से पहले छात्र ने अपने घर में दादा-दादी की हत्या की थी। बाद में दोनों के शव घर से बरामद हुए।

पुलिस ने बताया कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई 9 एमएम पिस्टल छात्र के दादा की थी, जो खुद शिक्षक थे। हमले के बाद आरोपी छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पटना-एक्सीडेंट में युवक की मौत पर बवाल, 10 गाड़ियां फूंकीं

9 थानों की फोर्स मौके पर

पटना,एजेंसी। पटना में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए। घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के जीरो माइल के पास शुक्रवार सुबह की है, जहां तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने उस बस को आग लगा दी।

फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने उसे रोक दिया। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तनाव और बढ़ गया। गुस्साई भीड़ ने 2 पुलिस गाड़ियों, बसों और बाइक समेत करीब 10 वाहनों में आग लगा दी। ट्रैफिक पुलिस पोस्ट जला दी। नेशनल हाईवे-30 पर जाम लगा दिया। पत्रकारों से मारपीट की। मौके पर 9 थानों की पुलिस तैनात की गई है।

उत्तराखंड में बद्रीनाथ-गंगोत्री हाईवे बंद

दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरा

» नोएडा में एंबुलेंस फंसी यूपी के 30 गांवों में बाढ़

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली-NCR में दो दिन से तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे कई जगह जाम लग गया है। नोएडा के सेक्टर-95 में एक एंबुलेंस पानी में फंस गई।

गुरुवार को द्वारका सेक्टर-25 में तेज बारिश के दौरान एक युवक खुले नाले में गिरकर तेज बहाव में बह गया। 7 घंटे तक रेस्क्यू अभियान के बावजूद युवक नहीं मिला।

उत्तराखंड में लगातार बारिश से अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी समेत छह नदियां खतरे के स्तर पर बह रही हैं। हरिद्वार-ऋषिकेश में घाट और मंदिर डूब गए हैं। रुद्रप्रयाग में स्कूल बंद हैं। राज्य की 132 सड़कें और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। 33 गांवों और 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया। बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं।

मानसून अब भी कमजोर, सामान्य से 68 फीसदी कम बारिश: बारिश के बावजूद इस बार नोएडा में मानसून की रफ्तार सामान्य से काफी धीमी बनी हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 6 अगस्त तक जिले में केवल 77.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य तौर पर करीब 244 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी।

असम: बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हुई... असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। दो और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 97 हो गई है। राज्य के 15 जिलों में 1.68 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट सबसे ज्यादा प्रभावित

यानी अब तक लगभग 68 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने पर ही इस कमी की कुछ भरपाई हो सकेगी।

पीएम मोदी ने युवाओं से हैंडलूम-डे मनाने की अपील की

● कहा- फ्रेंडशिप डे जैसा उत्साह दिखाएं ● हैंडलूम खरीदें और 'गेट रेडी विद मी' वीडियो बनाएं

नई दिल्ली,एजेंसी। पीएम मोदी ने गुरुवार रात इंस्टाग्राम पर देश के युवाओं से हैंडलूम डे पर भारत के हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने की अपील की। पीएम ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे हैंडलूम डे के बारे में बताते नजर आए। साथ ही उन्होंने यूथ इस दिन को GRWM ट्रेंड यानी गेट रेडी विद मी वीडियो के साथ सेलिब्रेट करने कहा।

पीएम मोदी वीडियो में कह रहे हैं- 'साथियों, 7 अगस्त 1905 का दिन हमें भूलना नहीं है। इस दिन देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन-जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सभी ने फ्रेंडशिप डे मनाया।'

पीएम ने कहा- 'मैं आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमें उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से कपड़े बनाते हैं। घरों में लूम पर काम करते हैं। उनके काम को बढ़ावा देना।' मोदी ने के अपील की- 'आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें। उसका एक वीडियो बनाएं और देश-दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें। ताकि हमारे बुनकर परिवारों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे मनाएं।'

पीएम ने कहा- हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें... वीडियो में पीएम कह रहे हैं- 'आप भी हैंडलूम की इस वैरायटी के साथ GRWM वीडियो बनाकर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इन छोटे-छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना है।'

40 साल बाद बोफोर्स केस बंद:सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी याचिका खारिज की

● घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हारे थे

नई दिल्ली,एजेंसी। करीब 40 साल पुराने बोफोर्स घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आखिरी याचिका भी खारिज कर दी। इसके साथ ही अब यह मामला पूरी तरह खत्म हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस केस में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 2005 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील भी सुनने से मना कर दिया, जिसमें हिंदुजा ब्रदर्स और बोफोर्स कंपनी को बरी कर दिया गया था।

1987 में खुलासा हुआ कि इस सौदे को हासिल करने के लिए कथित रूप से कमीशन (रिश्वत) दिया गया। घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार गए थे। इसके बाद यह मामला देश के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में शामिल हो गया।

क्या था बोफोर्स घोटाला... यह मामला 1986 में भारत सरकार और स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के बीच हुई 1,437 करोड़ रुपए की तोप खरीद डील से जुड़ा है।

सीबीआई का दावा: नीट पेपर लीक साजिश महीनों पहले हुई

एनटीए एक्सपर्ट्स पेपर तैयार करते समय सवाल याद कर लेते थे, छात्रों तक वॉट्सएप-टेलीग्राम से पहुंचा

नई दिल्ली,एजेंसी। NEET-UG 2026 पेपर लीक की साजिश परीक्षा से कई महीने पहले रची गई थी। NTA के एक्सपर्ट्स ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवाल याद कर लिए थे। CBI ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्जशीट में यह दावा किया है।

चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई थी। इसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई। इसके मुताबिक, एक्सपर्ट्स NTA ऑफिस से होटल लौटकर याद किए गए सवाल पर्चियों पर लिखते थे। इसके बाद इन्हें बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाता था।

CBI ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें NTA के तीन एक्सपर्ट्स शामिल हैं। आरोप है कि तीनों ने पेपर तैयार करने और मॉडरेशन के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर पेपर लीक किए। लीक पेपर टेलीग्राम, वॉट्सएप, PDF और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी फैलाए गए।

साजिश: महीनों पहले नेटवर्क खड़ा किया... CBI की चार्जशीट के मुताबिक, NEET पेपर लीक किसी एक व्यक्ति की साजिश नहीं थी, बल्कि NTA एक्सपर्ट्स, प्राइवेट कोचिंग संचालकों, बिचौलियों और कुछ छात्रों की मिलीभगत से पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। एजेंसी के अनुसार, परीक्षा से कई महीने पहले ही कोचिंग संचालकों और बिचौलियों ने NTA के तीनों एक्सपर्ट्स से संपर्क साध लिया था। इनके बीच लगातार बातचीत, मुलाकातें और पैसों का लेन-देन हुआ, जिसके जरिए पेपर लीक की पूरी साजिश रची

हूती विद्रोहियों का यमन और सऊदी अरब पर हमला

यमन के 58 सैनिकों की मौत, सऊदी में 11 घायल, कई जगह आग

तेहरान,एजेंसी। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को सऊदी अरब और यमन में एक साथ बड़े हमले किए। पहला हमला यमन सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हुआ, जिसमें 58 सैनिकों की मौत हुई और दर्जनों घायल हो गए। यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सही समय और सही जगह पर जवाब दिया जाएगा। दूसरा हमला सऊदी के नजरान में हुआ, जिसमें 11 नागरिक घायल हुए। इनमें 7 सऊदी, एक यमनी, दो मिस्री, एक पाकिस्तानी नागरिक है। वहीं, एक 4 साल का एक बच्चा भी घायल हुआ है।

हमलों के बाद नजरान के कई हिस्सों में आग लग गई। हूती (अंसार अल्लाह) यमन का शिया विद्रोही संगठन है। 2014 में उसने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। तब से वह यमन की सरकार और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान हूतियों को हथियार, ड्रोन और मिसाइल तकनीक मुहैया कराता है।

ईरान की जंग में हूती क्यों कूदे... यमन के हूती विद्रोहियों के ताजा हमले सिर्फ वहां के गृहयुद्ध तक सीमित नहीं हैं। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के साथ हूती भी हमले तेज कर रहे हैं। इसकी वजह ईरान और हूतियों के बीच लंबे समय से बने रिश्ते हैं।

स्वदेशी पर जोर

3.25 लाख करोड़ का मेगा सौदा

फ्रांस ने भारत को सौंपा राफेल विमानों के निर्माण का प्रस्ताव

नई दिल्ली,एजेंसी। 114 राफेल जेट विमान सौदे में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत फ्रांस ने भारत को इस सौदे के लिए विस्तृत तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमान का बड़े पैमाने पर स्थानीय निर्माण और उत्पादन शामिल होगा।

राफेल विमान भविष्य में भारतीय वायु सेना के मुख्य आधारों में से एक बनने की संभावना है। इसे 2012 में रक्षा मंत्रालय द्वारा एक लंबे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बाद चुना गया था।

फ्रांसीसी अधिकारियों ने 114 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए भारतीय अनुरोध पत्र का जवाब प्रस्तुत किया है। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग और भारतीय वायु सेना द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष फ्रांसीसी प्रस्ताव का बारीकी से विश्लेषण करेगा। सौदे के इस प्रस्ताव में भारतीय हथियारों जैसे कि अस्त्र हवा से हवा में मिसाइलों के विभिन्न रूपों में स्वदेशी सामग्री को एकीकृत करने की भारतीय मांग शामिल है।

फ्रांसीसी पक्ष को भारत में स्थानीय उद्योग भागीदार के साथ 114 में से 94 विमान का निर्माण करना है। यह कार्य फ्रांसीसी डसाल्ट एविएशन के सभी भागीदारों द्वारा किया जाएगा, जिसमें मिसाइल निर्माता एमबीडीए, इंजन निर्माता सफ्रान और थेल्स शामिल हैं। इस सौदे में स्वदेशीकरण की एक महत्वपूर्ण मात्रा की उम्मीद है। यह डील भारतीय रक्षा उद्योग के खिलाड़ियों जैसे कि टाटा, लार्सन और टुब्रो और अन्य के लिए लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये के अवसर प्रदान कर सकती है। भारत ने इस वर्ष मई में भारतीय वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू जेट के लिए फ्रांस को मेगा सरकारी सौदे के लिए अनुरोध पत्र जारी किया था।

केंद्र का हलफनामा- एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं

सुप्रीम कोर्ट से कहा- यह सिद्धांत सिर्फ ओबीसी और एसईबीसी पर लागू; याचिकाएं खारिज की जाए

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। सरकार ने उन जनहित याचिकाओं (PIL) का विरोध किया है, जिनमें SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में अधिक न्यायसंगत आरक्षण नीति बनाने की मांग की गई है।

केंद्र ने कहा कि याचिकाओं में संविधान के तहत किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जिक्र नहीं है। साथ ही, मौजूदा कानून में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि क्रीमी लेयर का नियम SC-ST पर लागू होता है। सरकार के मुताबिक, यह अवधारणा सिर्फ OBC और SEBC आरक्षण से जुड़ी है।

याचिका में मांग- संपन्न एससी-एसटी परिवारों को आरक्षण का लाभ न मिले: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 अगस्त को रमाशंकर प्रजापति और अन्य की जनहित याचिकाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया कि अगर किसी एससी-एसटी परिवार का सदस्य पहले ही संवैधानिक या वरिष्ठ सरकारी पद हासिल कर चुका है, तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इससे आरक्षण का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक ज्यादा समान रूप से पहुंच सकेगा। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उप-श्रेणी (सब-कैटेगरी) बनाकर उन्हें प्रवेश और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की भी मांग की है।

केंद्र ने यह भी कहा कि याचिका स्थापित कानून की अनदेखी करती है। सरकार ने इंदिरा साहनी (मंडल आयोग) मामले का हवाला देते हुए कहा कि SC, ST और OBC की पहचान ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर होती है, सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं।

केंद्र ने कहा- सिर्फ संसद को एससी-एसटी सूची में बदलाव का अधिकार... सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि SC और ST की सूची में किसी भी तरह का बदलाव केवल संसद ही कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत किसी जाति या जनजाति को सूची में शामिल करने या हटाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है।

सरकार बोली- कल्याणकारी योजनाओं में पहले से आय सीमा लागू: केंद्र ने कहा कि SC, ST और SEBC के लिए चलाई जा रही अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं में पहले से आय सीमा लागू है, ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई ने याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली,एजेंसी। सीबीआइ ने कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाने वाले भाजपा के सदस्य विग्नेश शिशिर को सोमवार को पेश होने के लिए कहा है।

इस बारे में पूछे जाने पर शिशिर ने बताया कि उन्हें सीबीआइ कार्यालय बुलाया गया है। उन्होंने यह कहते हुए कोई और जानकारी देने से इन्कार कर दिया कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

12 मई को हुई थी सुनवाई: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 12 मई को इस मामले में बंद कमरे में करीब दो घंटे तक सुनवाई की थी। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई को

उपलब्ध कराए गए आदेश में न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने कहा था कि सीबीआइ ने सूचित किया है कि उसे याचिकाकर्ता की शिकायत मिल गई है और वह आठ सप्ताह के भीतर अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी।

इससे पहले के आदेश में न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने कहा था कि यदि याचिकाकर्ता शिशिर की शिकायत प्राप्त हुई है तो आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जा सकता है।

पीठ ने सीबीआइ और ईडी के अलावा केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) को भी राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

शिशिर ने लगाया ये आरोप... शिशिर ने आपराधिक रिट याचिका में गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने आय से अधिक संपत्ति एकत्रित की है। याचिका में इस मामले की जांच सीबीआइ और ईडी से कराने का अनुरोध किया गया

रानी गार्डन में डीडीए का बुलडोजर एक्शन, 50 अवैध झुग्गियां और नर्सरी ध्वस्त

नईदिल्ली, एजेंसी। रानी गार्डन में दो दिनों तक डीडीए ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसी 50 झुग्गियों व नर्सरी को धवस्त कर दिया। अवैध रूप से बनी पार्किंग को भी हटा दिया गया है। इस जमीन पर वर्षों से लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस जमीन पर स्टे लगाया हुआ था। स्टे हटते ही डीडीए ने जिला प्रशासन व दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब तीन बीघा जमीन को खाली करवाया गया है। डीडीए ने इस जमीन पर अपने विभाग के बोर्ड लगा दिए हैं। एसडीएम गांधी नगर जितेंद्र सिंह ने बताया कि डीडीए की करोड़ों रुपये की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। कड़कड़डूमा कोर्ट से स्टे हटते ही डीडीए ने बुधवार व बृहस्पतिवार दो दिनों तक यहां कार्रवाई की। बुलडोजर के जरिये अवैध झुग्गियों को हटाया। अवैध पार्किंग को हटाया गया। अवैध नर्सरी को भी हटा दिया गया है। जमीन पर जगह-जगह मशीनों की मदद से गढ्डे कर दिए हैं। पूरी तरीके से डीडीए ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। किसी तरह का विरोध न हो, इसके लिए पुलिस तैनात की गई है। कुछ ही दिनों में डीडीए रानी गार्डन में दूसरी जमीन पर कार्रवाई करेगा।

महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा टैक्सी ड्राइवरों ने सीखी कामकाजी मराठी, अब स्थानीय भाषा में करेंगे बात

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक मई 2026 से सभी टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए राज्य की आधिकारिक भाषा में बुनियादी दक्षता अनिवार्य किए जाने के बाद अब तक एक लाख से अधिक गैर-मराठी चालकों ने व्यावहारिक मराठी भाषा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। यह जानकारी महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी। मंत्रालय में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सरनाईक ने एप आधारित टैक्सी चालकों समेत अन्य सभी चालकों से 15 अगस्त तक अपना मराठी प्रशिक्षण पूरा करने की अपील की। राज्य सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि राज्य में आटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए यात्रियों से मराठी में संवाद करना अनिवार्य होगा। उनके मराठी भाषा ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र दिवस (एक मई) के अवसर पर बालासाहेब ठाकरे मराठी शिकवणी अभियान शुरू किया गया था। इसके तहत प्रवासी चालकों के लिए मराठी भाषा का विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यह अभियान राज्य के मराठी भाषा विभाग व मुंबई मराठी साहित्य संघ और कोंकण मराठी साहित्य परिषद जैसे साहित्यिक निकाय के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान को राज्यभर में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

हिमाचल में आफत की बारिशः 145 सड़कें बंद, 224 ट्रांसफार्मर ठप; अगले 48 घंटे रहेंगे मुश्किल भरे

शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में हुई मूसलाधार वर्षा ने राज्यभर में भारी तबाही मचाई है। मौसम केंद्र शिमला की रिपोर्ट के अनुसार, धर्मशाला में सर्वाधिक 79 मिलीमीटर जोगिंदरनगर में 76, मंडी में 63.4 और राजधानी शिमला में 54.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

145 सड़कें यातायात के लिए बंदः 7 अगस्त सुबह 10 बजे तक प्रदेश भर में 145 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो चुकी हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 66 सड़कें प्रभावित हुई हैं, जबकि कुल्लू में 31 और सिरमौर में 28 सड़कें बंद हैं। वर्षा व भूस्खलन के कारण बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश में 224 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं, जिनमें अकेले मंडी जिले के 182 ट्रांसफार्मर शामिल हैं।

कानपुर एक्सप्रेसवे के आउटर रिंग रोड निर्माण में भी बरती गई थी अनदेखी, पीएनसी को मिला था नोटिस

लखनऊ, एजेंसी। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को भले ही नान परफार्मर की श्रेणी में डालने को लेकर एनएचएआइ ने मोर्थ को संस्तुति भेज दी है, लेकिन बीते दो वर्षों पर नजर डालें तो एनएचएआइ इस कंपनी की करतूतों पर लगातार मेहरबान दिखाई देता है। आउटर रिंग रोड की ही बात करें तो अगस्त 2024 में इस लखनऊ आउटर रिंग रोड को बनाते वक्त भी एनएचएआइ ने पीएनसी को नोटिस थमाया था। उस समय कंपनी ने बेहटा गांव से सीतापुर रोड तक (31.74 किमी.) तक फोर लेन सड़क बनाने का काम किया था, जिसमें कई खामियां मिली थी। तब भी मामला नोटिस तक ही सीमित रह गया और एनएचएआइ ने कार्रवाई को लेकर कुछ भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। हालांकि सूत्र बताते हैं कि यह नोटिस ऊंचाहार से आने वाली फ्लाई ऐश को लाने में पीएनसी के ट्रकों से सड़क खराब होने को लेकर दिया गया था।

अब एक बार फिर स्थिति उसी मोड़ पर आ गई है जब कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी पीएनसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि यह कार्रवाई एक सप्ताह पहले ही हो चुकी है, जिसे एनएचएआइ लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी गौतम विशाल ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया। उधर पीएनसी ने जवाब देने के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए एनएचएआइ को पत्र लिखा है। एनएचएआइ का खराब सड़क बनाने वाली कंपनियों से पुराना नाता रहा है। इसमें 105 किमी. आउटर रिंग रोड को बनाने वाली डीआर अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सबसे आगे है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के ड्रीम प्रोजेक्टों में शामिल रहे आउटर रिंग रोड को दो साल में बनाना था और डीआर अग्रवाल कंपनी ने साढ़े चार साल लगा दिए थे।

एनएचएआइ के तत्कालीन परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया ने विलंब व गुणवत्ता की अनदेखी करने पर डीआर अग्रवाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर 25 करोड़ का जुर्माना (एलडी यानी लिक्विडिटी डैमेज) लगाया था। इसमें सड़क के निरीक्षण में खामियां मिली थी, इस पर 1.22 करोड़ का अलग से जुर्माना लगाया था। यही नहीं परियोजना निदेशक को निरीक्षण के दौरान सीतापुर रोड से कुर्सी रोड के बीच कई स्थानों पर गड्ढे मिले थे। इसमें तीसरी कंपनी सद्भावना इंजीनियर्स लि.को भी नोटिस दी गई थी। अब इन सभी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है, इस पर एनएचएआइ चुप्पी साधे हुए है वहीं पीएनसी को एक तरफ नान परफार्मर का नोटिस दिया गया है तो दूसरी तरफ पीएनसी कंपनी अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि उसने मध्यप्रदेश में जावरा-नयागांव का 127 किमी. का फोर लेन, ग्वालियर-भिंड एनएच 92, यूपी में गाजियाबाद-अलीगंज सेक्शन, कानपुर-कबराई सेक्शन, आगरा- ग्वालियर सेक्शन, पंजाब में पानीपत-जालांधर सेक्शन सहित हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे बनाने का अनुभव है। यही नहीं एयरपोर्ट रनवे, ब्रिज निर्माण, पावर सेक्टर में भी कंपनी अभी काम कर रही है। इस संबंध में जब पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर वी कुंडू से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

राजस्थान में मूक-बधिर छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन, गहलोत और जूली पहुंचे स्कूल

जयपुर, एजेंसी। जयपुर के आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर उच्च माध्यमिक स्कूल में दिव्यांग छात्र-छात्राओं ने पीने के पानी के संकट, जर्जर स्कूल भवन, शौचालयों की बदहाल स्थिति और शिक्षकों द्वारा तय समय पर पढ़ाई नहीं करवाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र-छात्राओं ने स्कूल के बाहर रास्ता रोक लिया, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद खाली करवाया। सूचना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी स्कूल में पहुंचे। छात्र-छात्राओ ने आरोप लगाया कि कई ऐसे शिक्षक स्कूल में तैनात हैं, जिन्हें साइन भाषा नहीं आती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र-छात्राएं बीमार भी हो गए, जिनका चिकित्सकों ने उपचार किया। हंगामा बढ़ता देखकर जिला कलेक्टर संदेश नायक एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्कूल के निरीक्षण में खामियां मिलने के बाद प्रधानाध्यापक भारत जोशी को हटाकर पदस्थापन आदेश की प्रतिक्षा में रखने का आदेश जारी किया है।

चंडीगढ़ में स्मार्ट पार्किंग का देख लो हाल शुल्क पूरा, सुरक्षा जीरो; चोरी हुई तो नगर निगम ने झाड़े हाथ

चंडीगढ़, एजेंसी। शहर में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम पर सवाल उठे हैं। आपका वाहन चोरी होता है तो इसके लिए निगम जिम्मेदार नहीं है। नगर निगम पार्किंग शुल्क तो पूरे अधिकार से वसूलता है, लेकिन उसी पार्किंग से वाहन चोरी हो जाए तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यानी नागरिक पैसे भी दें, वाहन की सुरक्षा का भरोसा भी न मिले और चोरी होने पर नुकसान भी खुद उठाएं। वहीं अगर पार्किंग की पर्ची खो जाए तो वाहन मालिक से 100 रुपये जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन यदि लाखों रुपये का वाहन पार्किंग से चोरी हो जाए तो निगम लिखित में कह देता है कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सवाल यह है कि जब सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर पार्किंग शुल्क आखिर किस बात का लिया जा रहा है।

सुबह पार्किंग में लगाई एक्टिवा, शाम को गायब मिली: सेक्टर-39 निवासी मोहित गुप्ता ने बताया वह एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, 23 जुलाई को रोज की तरह अपनी एक्टिवा लेकर सेक्टर-17 पहुंचे। सुबह करीब साढ़े नौ बजे उन्होंने ब्लिंकइट कार्यालय के सामने स्थित नगर निगम की अधिकृत पार्किंग में वाहन खड़ा किया और शुल्क भी जमा किया। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद लौटे तो पार्किंग से उनकी एक्टिवा गायब थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस केवल आनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सलाह देकर चली गई। मोहित ने जब पार्किंग संचालक से जवाब मांगा तो उन्हें साफ कह दिया गया कि पार्किंग से वाहन चोरी होने पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। यानी पार्किंग शुल्क लेने वाले हाथ खड़े कर गए और पीड़ित अपने हाल पर छोड़ दिया गया।

नगर निगम का जवाब और भी चौंकाने वाला: पीड़ित ने नगर निगम, उपायुक्त कार्यालय और प्रशासन को लिखित शिकायत देकर मुआवजे की मांग की। नगर निगम ने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया कि पार्किंग में वाहन चोरी होने पर निगम की कोई जवाबदेही नहीं है। वहीं उपायुक्त कार्यालय ने शिकायत संबंधित थाने को भेज दी, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह मामला नगर निगम की पार्किंग नीति पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

हर दिन हजारों वाहन, लेकिन सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं: सेक्टर-17 सहित शहर की विभिन्न निगम पार्किंगों में प्रतिदिन हजारों वाहन खड़े होते हैं। लोग यह मानकर शुल्क देते हैं कि उनका वाहन सुरक्षित रहेगा। निगम का जवाब यह संकेत देता है कि पार्किंग शुल्क केवल वाहन खड़ा करने की कीमत है, उसकी सुरक्षा की नहीं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि पार्किंग परिसर में सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मी और शुल्क वसूली के बावजूद वाहन सुरक्षित नहीं है, तो नागरिक आखिर किस भरोसे अपनी गाड़ी वहां खड़ी करें।

सिर्फ वसूली कर रहा एमसी : फॉसवेकः फॉसवेक अध्यक्ष बलजिंदर सिंह बिट्टू का कहना है कि शहर की पेड पार्किंग सिर्फ एंट्री शुल्क वसूल करने की तरह चल रही है जबकि भीतर वाहनों की सुरक्षा के लिए कोई तैनात नहीं होता यहां तक कि वाहन चालकों की मदद के लिए भी कोई कर्मचारी तैनात नहीं होता है। ऐसे में जब सुरक्षा की जिम्मेदारी नगर निगम लेने को तैयार नहीं है तो फिर वसूली किस बात की कर रहा है।

छात्र ने स्कूल में बरसाईं गोलियां दो की मौत और 15 घायल फिर खुद की आत्महत्या

बैंकाक, एजेंसी। थाईलैंड के एक स्कूल में शुक्रवार को गोलीबारी हुई। इसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। वहीं, कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह घटना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में स्थित नोनथाबुरी जिले के देबसिरिन स्कूल में हुई।कब हुई यह घटना अधिकारियों ने बताया कि एक छात्र ने स्कूल में गोलीबारी की, जिसके बाद छात्र और शिक्षक भागने लगे और आपातकालीन बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। यह घटना स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 10 बजे हुई, जब पोह टेक तुंग फाउंडेशन के स्वयंसेवकों को प्रसिद्ध माध्यमिक विद्यालय के अंदर गोलीबारी की सूचना मिली।कितने लोगों की मौत की पुष्टि हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन द बैंकॉक पोस्ट और थाई एनक्वायरर की रिपोर्टों में कहा गया है कि कम से कम दो मौतों की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच, पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि हमलावर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।सुरक्षाकर्मियों ने जनता से क्या अपील की आपातकालीन कर्मचारियों द्वारा प्रसारित तस्वीरों में, एम्बुलेंस के घटनास्थल पर पहुंचने के साथ ही छात्र स्कूल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। घटना का लाइव प्रसारण भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और सुरक्षाकर्मियों ने जनता से घटना का लाइव प्रसारण न करने का अनुरोध किया है।फरवरी में क्या हुआ था यह घटना फरवरी में हुई एक स्कूल गोलीबारी में एक शिक्षक की मौत और एक छात्र के घायल होने के कुछ महीनों बाद हुई है। फरवरी में हुई घटना में, हमलावर की पहचान 18 वर्षीय युवक के रूप में हुई,। जिसने सोंगखला प्रांत के फातोंग प्रथान खिरीवत स्कूल में गोलीबारी की थी। इस घटना के दौरान छात्रों और शिक्षकों को भी बंधक बना लिया गया था, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छुड़ा लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, थाईलैंड में इस क्षेत्र में बंदूक रखने की दर सबसे अधिक है, जहां अनुमानित तौर पर लगभग 10 मिलियन आग्नेयास्त्र प्रचलन में हैं, जो प्रति सात निवासियों पर एक के बराबर है। बंदूक कानूनों को सख्त करने के पूर्व वादे देश में बार-बार होने वाली गोलीबारी की घटनाओं को रोकने में विफल रहे हैं।

क्या जल्द खत्म होगा पश्चिम एशिया का संघर्ष ट्रंप ने किया बड़ा दावा हथियारों की कमी पर भी बोले

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ शुरू किया गया अभियान बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मौजूदा युद्ध अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और उन्हें उम्मीद है कि यह जल्द समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उन खबरों को भी खारिज किया, जिनमें अमेरिकी सेना के पास जरूरी हथियारों और गोला-बारूद की कमी होने की बात कही जा रही थी।ट्रंप ने युद्ध जल्द खत्म होने का दिया संकेतडोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया था। उनके अनुसार, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके। उन्होंने कहा 'मुझे लगता है कि यह युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह अब ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है।' हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि युद्ध समाप्त करने के लिए आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी।ईरान-ओमान वार्ता पर ट्रंप ने साधी चुप्पीअपने बयान के दौरान ट्रंप ने ईरान और ओमान के बीच जारी बातचीत पर कोई टिप्पणी नहीं की। दिनों में ऐसी कई रिपोर्टें सामने आई थीं,

जिनमें दावा किया गया था। कि अमेरिकी सेना के पास ईरान में युद्ध संचालन और अन्य संभावित सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक गोला-बारूद और मिसाइलों की कमी हो रही है। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना के पास किसी भी महत्वपूर्ण सैन्य अभियान के लिए जरूरी हथियारों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पैट्रियट मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल, साइडवाइंडर मिसाइल और सामान्य गोला-बारूद की मांग जरूर बढ़ी है, लेकिन इन सभी हथियारों का उत्पादन तेज गति से बढ़ाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि इन हथियारों के उत्पादन पर आने वाले खर्च को अमेरिकी कांग्रेस को वहन करना होगा।

जन्म से मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता पर डोनाल्ड ट्रंप का नया वार बर्थ टूरिज्म रोकने के लिए दो आदेश जारी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को सीमित करने और 'बर्थ टूरिज्म' पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को दो नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कुछ सप्ताह पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ट्रंप के पहले आदेश को खारिज कर दिया था।क्या है पहला आदेशपहले आदेश का उद्देश्य उन लोगों पर कार्रवाई करना है जो केवल बच्चे को अमेरिका में जन्म दिलाने के लिए वहां आते हैं। इसे 'बर्थ टूरिज्म' कहा जाता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोग पर्यटन वीजा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनका असली मकसद बच्चे को अमेरिका में जन्म देकर उसे अमेरिकी नागरिक बनवाना होता है।दूसरे आदेश में क्या हैदूसरे आदेश में उन लोगों की श्रेणियों का दायरा बढ़ाया गया है, जिन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए अयोग्य माना जाएगा। इसमें विदेशी सरकारों के लिए काम करने वाले या उनकी ओर से लॉबिंग करने वाले लोगों के बच्चों

समेत कुछ अन्य श्रेणियां शामिल की गई हैं।सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश को किया था खारिज30 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पहले कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि 100 वर्षों से चली आ रही संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिलती है।ट्रंप बोले- सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्णओवल ऑफिस में आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था और उनकी सरकार अब उसमें जरूरी बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का जन्मसिद्ध नागरिकता पर फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इसलिए हम इसमें आवश्यक बदलाव कर रहे हैं'।14वां संशोधन क्या कहता हैअमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन, जिसे 9 जुलाई 1868 को लागू किया गया था, अमेरिका में जन्म लेने या नागरिकता प्राप्त करने वाले सभी लोगों को अमेरिकी नागरिक मानता है। यह प्रावधान गृहयुद्ध के बाद पूर्व गुलामों को नागरिकता देने के लिए लाया गया था। ट्रंप ने कहा कि यह कानून उस समय की जरूरत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाकर 'बर्थ टूरिज्म' का कारोबार चला रहे हैं।व्हाइट हाउस का क्या तर्क हैव्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि कई लोग पर्यटक बनकर अमेरिका आते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य बच्चे को अमेरिका में जन्म दिलाना होता है ताकि उसे स्वतः नागरिकता मिल जाए। उनके अनुसार, इससे ऐसे परिवारों को भविष्य में सरकारी योजनाओं, अन्य सुविधाओं और नागरिक अधिकारों तक पहुंच मिल जाती है।किन लोगों के बच्चों पर असर पड़ सकता हैनए आदेश के अनुसार कुछ श्रेणियों के लोगों के बच्चों को नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने पर रोक लगाने की बात कही गई है। इनमें शामिल हैं: बर्थ टूरिज्म के जरिए अमेरिका पहुंचने वाले लोगों के बच्चे। आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों के बच्चे। विदेशी सरकारों के कर्मचारियों के बच्चे। कुछ अमेरिकी क्षेत्रों में जन्मे ऐसे बच्चे, जहां संघीय कानून के तहत स्वतः नागरिकता नहीं मिलती।विशेषज्ञों ने बताया असंवैधानिकआव्रजन कानून के विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति ट्रंप के नए आदेशों का विरोध किया है। न्यूयॉर्क के इमिग्रेशन वकील साइरस मेहता ने कहा कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक लेन-देन जैसी परिभाषा बहुत अस्पष्ट है और इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। वहीं, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जन्मसिद्ध नागरिकता संविधान द्वारा सुरक्षित अधिकार है। ऐसे में ट्रंप का नया आदेश भी अदालत में टिकना मुश्किल होगा।क्या कहते हैं आंकड़ेमाइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार, हर साल अमेरिका में 'बर्थ टूरिज्म' के जरिए करीब 22,000 से 26,000 बच्चों का जन्म होने का अनुमान है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में विदेशी पते वाली माताओं से 9,600 बच्चों का जन्म अमेरिका में दर्ज किया गया था।

मेटा को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका बच्चों की सुरक्षा में चूक पर 5400 करोड़ चुकाने का आदेश

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा को उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 567 मिलियन डॉलर (करीब 5400 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला उस ऐतिहासिक मुकदमे के दूसरे चरण में आया है, जिसमें मार्च में मेटा को हार का सामना करना पड़ा था। जज ब्रायन बिडशाइड के फैसले के अनुसार, कुल राशि में से 42 करोड़ डॉलर (420 मिलियन डॉलर) युवाओं के इलाज और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर खर्च किए जाएंगे। शेष राशि अगले पांच वर्षों में जागरूकता अभियान, रोकथाम कार्यक्रम, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य संबंधित खर्चों के लिए उपयोग की जाएगी।मुकदमे के पहले चरण में जूरी ने मेटा पर 37.5 करोड़ डॉलर (375 मिलियन डॉलर) का सिविल जुर्माना लगाया था। जूरी ने माना था कि कंपनी को यह जानकारी थी कि उसके प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही, कंपनी पर अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जानकारी छिपाने का भी आरोप माना गया था।क्या अदालत ने मेटा में बड़े बदलाव करने के निर्देश दिएमुकदमे के दूसरे चरण में अभियोजन पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया था कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर लत पैदा करने वाले फीचर्स को सीमित किया जाए।

भुईमाड़ से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ, विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याए

हर शुक्रवार गांवों में पहुंचेंगे अधिकारी, योजनाओं का लाभ और शिकायतों का होगा मौके पर समाधान

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 का शुभारंभ शुक्रवार को कुसमी विकासखंड के ग्राम भुईमाड़ से किया गया शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और प्रशासन को सीधे जनता के बीच ले जाने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान के तहत केशलार, कैरल, गैवट्या, सोनगढ़, अमरोला एवं भुईमाड़ ग्रामों के लिए संयुक्त जनसंवाद शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम है उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा प्रशासन को गांव-गांव तक पहुंचाना है उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी भी योजना के लाभ से वंचित है तो इस अभियान के माध्यम से उसकी समस्या का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा विधायक ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार अधिकारी अपने कार्यालयों से निकलकर गांवों और शहरी क्षेत्रों में जनसंवाद शिविर लगाएंगे इन शिविरों में आयुष्मान भारत कार्ड, समग्र आईडी ई-केवाईसी, किसान आईडी सहित विभिन्न शासकीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी उन्होंने ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक संख्या में शिविरों का लाभ उठाने की अपील की जनपद पंचायत कुसमी की अध्यक्ष श्यामवती सिंह ने विद्यालय में विद्यार्थियों से चर्चा कर शिक्षा व्यवस्था, साइकिल वितरण, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक मामलों में अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए वहीं उपखंड अधिकारी सागर जैन ने कहा कि यह अभियान प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने की प्रभावी पहल है और सभी अधिकारियों को शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना होगा इस अवसर पर जनपद पंचायत कुसमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अभियान के दौरान अधिकारियों ने विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र तथा शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुईमाड़ का भी निरीक्षण कर पेयजल, शौचालय, कक्षाओं की स्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए अभियान के शुभारंभ के साथ क्षेत्र में शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई।

8 अगस्त को सीधी दौरे पर रहेंगे प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, कई कार्यक्रमों में करेंगे सहभागिता

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल 8 अगस्त को एक दिवसीय प्रवास पर सीधी आएंगे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे जिले में विभिन्न शासकीय एवं सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री जायसवाल दोपहर 12:30 बजे सर्किट हाउस, सीधी पहुंचेंगे। यहां वे जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों तथा आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों से अवगत होंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे वे सरस्वती शिशु मंदिर, मड़रिया (सीधी) में आयोजित मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करेंगे इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा दोपहर 2 बजे प्रभारी मंत्री सर्किट हाउस में प्रबंध समिति की बैठक लेंगे। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा किए जाने की संभावना है इसके उपरांत दोपहर 3 बजे वे कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे बैठक में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 3:30 बजे प्रभारी मंत्री स्थानीय कार्यक्रम में भी सहभागिता करेंगे, जहां वे आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे इसके बाद सायं 5 बजे वे सीधी से बिजुरी (जिला अनूपपुर) के लिए प्रस्थान करेंगे प्रभारी मंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

15 अगस्त के तिरंगा पतंग मेले को यादगार बनाने जुटा हिन्दू धर्म परिषद, शहर की कई संस्थाओं ने दिया समर्थन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रीवा शहर में पहली बार आयोजित होने जा रहे तिरंगा पतंग मेला को भव्य और यादगार बनाने के लिए हिन्दू धर्म परिषद ने व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। परिषद के पदाधिकारी शहर के पतंगबाजों, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संगठनों से संपर्क कर उन्हें आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं यह आयोजन 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय (टीआरएस कॉलेज) मैदान में आयोजित होगा, जबकि प्रतिभागियों का पंजीयन दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा पंजीयन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा आयोजन के संयोजक एवं हिन्दू धर्म परिषद के संस्थापक नारायण डिगवानी, परिषद अध्यक्ष ऋषिशंकर मिश्रा तथा टीआरएस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के सदस्य राजेन्द्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रभक्ति के उत्सव के रूप में मनाना तथा युवाओं और नागरिकों को तिरंगे के सम्मान से जोड़ना है आयोजन में भाग लेने वाले सभी पतंगबाजों और प्रतिभागियों को विशेष रूप से अहमदाबाद से मंगाई गई तिरंगा पतंगें उपहार स्वरूप प्रदान की जाएंगी। साथ ही उन्हें स्वल्पाहार एवं सम्मान पत्र भी दिए जाएंगे कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी विशेष आकर्षण रहेगा। रिदम म्यूजिकल ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. विनोद तिवारी एवं महासचिव पियूष मिश्रा के मार्गदर्शन में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी, जिससे पतंगबाजों और उपस्थित नागरिकों में राष्ट्रप्रेम का उत्साह बढ़ेगा। आयोजन को लेकर शहर की कई संस्थाओं ने भी अपना सहयोग देने की घोषणा की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मोहन तिवारी अपने साथियों के साथ शामिल होंगे वहीं कलम परिवार के अध्यक्ष नागेन्द्र मिश्रा 'मणि' और महासचिव रामकृष्ण द्विवेदी ने देशभक्ति विषयक काव्य पाठ की जानकारी दी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी मंच के अवनीश शर्मा ने बताया कि मंच के सदस्य तिरंगा झंडों के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे इसके अलावा ब्रह्माकुमारी कला एवं संस्कृति प्रभाग, रीवा के संयोजक बी.के. प्रकाश ने भी अपने सभी सदस्यों के साथ आयोजन को सफल बनाने का भरोसा दिलाया इधर, विन्ध्य काव्य-साहित्य परिषद 'कलम परिवार' ने भी 17 अगस्त को शांतिधाम सभागार में तिरंगा ध्वज वंदना काव्य गोष्ठी आयोजित करने की घोषणा की है इस कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र के साहित्यकार राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं का पाठ करेंगे साथ ही वरिष्ठ राष्ट्रभक्त वैद्य बटुक प्रसाद त्रिपाठी के 80वें जन्मदिवस पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विशेष चर्चा भी होगी आयोजकों का कहना है कि दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान : हर पात्र तक योजनाओं का लाभ और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें - कमिश्नर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने रामपुर नैकिन विकासखंड के ग्राम बुढ़गौना में आयोजित जनसंवाद शिविर में शामिल होकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया इस अवसर पर कलेक्टर विकास मिश्रा भी मौजूद रहे कमिश्नर ने ग्रामीणों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य केवल शिकायतों का समाधान करना नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र हितग्राही तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने की अपेक्षा की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लक्षित रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन, नियमित प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, पोषण सेवाएं तथा संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि रोकी जा सकने वाली एक भी मातृ मृत्यु स्वीकार्य नहीं है उन्होंने जिले में सिकल सेल स्क्रीनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और विशेष अभियान चलाकर लक्षित समूह के प्रत्येक व्यक्ति की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लंबित शिकायतों पर भी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रत्येक शिकायत का व्यक्तिगत परीक्षण कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए कमिश्नर ने 'वॉश ऑन व्हील' पहल के प्रभावी संचालन पर बल देते हुए विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों तथा सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए इसके साथ ही उन्होंने बघवार स्थित खाद विक्रय केंद्र का निरीक्षण कर किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के निर्देश दिए।

सीधी में शिक्षा व्यवस्था शर्मसार : 4 महीने में सिर्फ 13 दिन स्कूल आए शिक्षक, फिर भी मिली पूरी 52,800 सैलरी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के सिहावल जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम डिहुली नंबर-4 स्थित प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दिनेश कोल पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं आरोप है कि शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आते थे कक्षा में ही शराब पीते थे और चार महीने में मात्र 13 दिन स्कूल आने के बावजूद उन्हें हर महीने 52,800 का पूरा वेतन जारी किया गया हाल ही में शिक्षक का कक्षा में शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया इसके बाद मौके पर पहुंची मीडिया टीम ने शिक्षक को स्कूल के एक कमरे में दरी बिछाकर सोते हुए पाया जगाने पर

वह लड़खड़ाते हुए उठे और बच्चों को पढ़ाने लगे इस दौरान उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा का नाम भी गलत लिख दिया ग्रामीण ग्यासुद्दीन अंसारी ने आरोप लगाया कि शिक्षक अक्सर जेब में शराब की बोतल लेकर स्कूल आते हैं और बच्चों के सामने ही शराब पीते हैं विद्यालय के बच्चों ने बताया कि शिक्षक जब भी स्कूल आते हैं, नशे की हालत में रहते हैं। कई बार वे कक्षा में गिर जाते हैं या उल्टी कर देते हैं अभिभावकों का कहना है कि इसी कारण कई परिवारों ने अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल से कटवाकर निजी स्कूलों में दाखिला करा दिया विद्यालय में पदस्थ दूसरे शिक्षक अशोक कुमार शर्मा के अनुसार, दो वर्ष पहले स्कूल में लगभग 200 छात्र अध्ययनरत थे लेकिन अब यह संख्या घटकर केवल 28 रह गई है। उन्होंने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर में दिनेश कोल की चार महीनों में केवल 13 दिन उपस्थिति दर्ज है जबकि संकुल स्तर से उनकी 100 प्रतिशत उपस्थिति भेजी जाती रही जिसके आधार पर उन्हें पूरा वेतन मिलता रहा।

हुनर को बाजार से जोड़कर महिलाओं की आय दोगुनी करें : शीलेन्द्र सिंह

भरतपुर हथकरघा सहकारी समिति का निरीक्षण, स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की सराहना; बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर दिया जोर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने भरतपुर स्थित हथकरघा सहकारी समिति का निरीक्षण कर स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया इस दौरान कलेक्टर विकास मिश्रा भी मौजूद रहे कमिश्नर ने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों का अवलोकन किया और उनकी मेहनत, कला एवं कौशल की सराहना की कमिश्नर शीलेन्द्र

सिंह ने कहा कि स्व-सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम हैं उन्होंने महिलाओं से अपनी आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित कर योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, नवाचार और प्रभावी विपणन के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई जा सकती है महिलाओं के हुनर को बाजार से जोड़ना समय की आवश्यकता है जिससे उनकी आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित हो सके निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजार के साथ-साथ बड़े शहरों और निजी बाजारों की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादों की गुणवत्ता, डिजाइन और पैकेजिंग में निरंतर सुधार किया जाए इससे उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे और बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। उन्होंने महिलाओं को केवल शासकीय मेलों और प्रदर्शनियों तक सीमित न रहने की सलाह देते हुए निजी क्षेत्र, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा बड़े बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा कि यदि उत्पाद बाजार की मांग के अनुरूप होंगे तो उन्हें व्यापक बाजार, बेहतर पहचान और अधिक आय प्राप्त होगी।

बघोर-मेढ़ौली से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ, विधायक विश्वामित्र पाठक बोले- कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहे

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के तहत शुक्रवार को सिहावल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेढ़ौली में संयुक्त जनसंवाद एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत बघोर, मेढ़ौली, गेरुआ एवं दुधमनिया के ग्रामीणों की समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए विभागवार पंजीयन के बाद कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों के समयबद्ध समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाकर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना है उन्होंने कहा कि यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा इसके माध्यम से अधिकारी नियमित रूप से गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी शिकायतों एवं मांगों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करेंगे विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचे और कोई भी नागरिक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना है इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराएं उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि कृषि सीजन के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि का स्वामित्व दिलाने, पात्र हितग्राहियों के संबल योजना, कर्मकार मंडल पंजीयन तथा आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को किसी भी योजना का लाभ पाने में अनावश्यक विलंब या परेशानी नहीं होनी चाहिए। विधायक विश्वामित्र पाठक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जले हुए ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विद्युत संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें जिससे शासन की योजनाओं का लाभ समय पर प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंच सके और आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर ग्रामीणों को आयुष्मान भारत योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व, कृषि, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई।

सीधी वृत्त की समीक्षा बैठक में राजस्व, सीएम हेल्पलाइन, लाइन लॉस और विद्युत चोरी पर दिए सख्त निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, रीवा की मुख्य अभियंता प्रमा पांडे ने सीधी वृत्त कार्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर राजस्व वसूली, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ता सेवाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में सीधी वृत्त के सभी कार्यालय प्रमुख, सहायक अभियंता एवं वितरण केंद्र प्रभारी उपस्थित रहे बैठक में मुख्य अभियंता ने राजस्व वसूली, बिलिंग एवं कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने, लाइन लॉस कम करने तथा बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अमिलिया एवं बहरी वितरण केंद्रों में अपेक्षाकृत कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जताते हुए निर्धारित लक्ष्य के साथ पिछले माह के बैकलॉग को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए साथ ही गलत बिजली बिलों से संबंधित मामलों का तत्काल निराकरण करने तथा सीआरपीयू सहित सभी प्रदर्शन संकेतकों में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया प्रमा पांडे ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 100 दिन से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का तीन दिवस के भीतर संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध समाधान विभाग की प्राथमिकता है इसके साथ ही खराब मीटरों को शीघ्र बदलने, ट्रिपिंग कम करने के लिए आवश्यक रखरखाव कार्य समय पर पूरा करने तथा निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश भी दिए बैठक में विद्युत चोरी के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण, नए प्रकरण दर्ज करने तथा कुर्की अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

पीएम की माफी के मायने

संपादकीय

प्रधानमंत्री मोदी ने उन बच्चों, छात्रों, युवाओं को माफ कर दिया है, जिन्होंने उन्हें और उनकी दिवंगत मां को भद्दी-भद्दी गालियां दी थीं। प्रधानमंत्री ने ईसा मसीह और महात्मा बुद्ध के 'क्षमा-याचना सिद्धांत' के आधार पर बच्चों को माफ किया है। यकीनन उन्हें सद्बुद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा है- 'मैं उनके आक्रोश को समझता हूं। कुछ शरारती बच्चों ने ये गालियां दी हैं। वे गुमराह हो गए हैं। उन्हें राह पर लाना हमारा ही काम है। बचपन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे नहीं जानते कि उनका विवेक क्या है। कुछ बेटियों ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह मेरे लिए एक 'सांस्कृतिक धक्का' है। फिर भी बच्चों को सजा देने, अदालतों के चक्कर कटवाने और प्रताड़ित करने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी।' बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने गालीबाज युवाओं को तो माफ कर दिया, क्योंकि वह देश में 'जेन-जी' का मूड भांप चुके थे। हालांकि ये गालीबाज युवा 'जेन-जी' के समग्र प्रतिनिधि नहीं हैं और न ही देश का युवा अपने प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें स्वीकृति, मान्यता देता है। दिल्ली के 'जंतर-मंतर' पर जो युवा-प्रदर्शन किया गया था, उसमें सभी वाकई 'जेन-जी' की जमात नहीं थे। उनमें 2873 आपराधिक आरोपित चेहरे भी थे, ऐसा पुलिस ने पहचान कर चिह्नित किया है। उस भीड़ में सपा, 'आप', चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और वामदलों के भेजे गए काडर भी थे। क्या प्रधानमंत्री उन्हें भी माफ कर देंगे, जिन्होंने पुलिस वालों के सिर फोडऩे और किसी भी तरह संसद भवन में घुसने की साजिशें तैयार की थीं? कुछ छात्रों, बच्चों ने हाथ जोड़ कर प्रधानमंत्री से माफी मांगी है और अपने अभद्र, अश्लील, अमर्यादित शब्दों के लिए शर्मिन्दगी महसूस की है। 'कॉकरोच' पार्टी के कुछ चेहरे प्रधानमंत्री के माफीनामे को खारिज कर रहे हैं। उनकी दलील है कि 50 फीसदी सांसदों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। भाजपा में भी ऐसे नेता हैं, जो गाली से बदतर व्यवहार करते हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। हम पाठकों के लिए एक तथ्य और प्रावधान स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 में 'अभिव्यक्ति की आजादी' का उल्लेख है, लेकिन वह निरंकुश, अपरिमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19 (2) में प्रावधान है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। मसलन-प्रधानमंत्री को या किसी को भी इस तरह गालियां देना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। 'कॉकरोच' प्रवक्ता सौरव दास इन गालियों को 'अपराध' ही नहीं मानते। कांग्रेस अध्यक्ष समेत पार्टी के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए 100 से अधिक अपशब्दों का बार-बार इस्तेमाल करते रहे हैं। यह कौन-सा और कैसा लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र में गालियां देने की भी स्वतंत्रता होती है? प्रधानमंत्री देश के निर्वाचित नेता हैं, न कि उन्होंने यह पद कब्जाया है। उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और पूरी सरकार का विरोध करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें, गालियां देने का औचित्य क्या है? उससे तो व्यक्ति का अपना चरित्र कलंकित होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के लिए 'आपत्तिजनक' शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्हें कौन समझा सकता है। वह खुद एक जिम्मेदार, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री के अघोषित निर्देश पर उन राज्यों की सरकारों और पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवाओं के खिलाफ प्राथमिकी और आपराधिक केस वापस लिए हैं या ऐसा निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा बच्चों को माफ करने की घोषणा की है, क्योंकि वह देश के सर्वप्रथम कार्यकारी प्रमुख हैं, बुजुर्ग हैं, संवैधानिक शक्तियां रखते हैं और एक राजनेता के तौर पर देश की 65 फीसदी से अधिक आबादी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यहां हम यह भी कहना चाहते हैं कि छात्रों, युवाओं और पुलिस-सुरक्षा बलों के जवानों, अधिकारियों के मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार और नागरिक अधिकार एक समान हैं। युवा घायल हुए हैं, तो यह भी चिंतनीय और निंदनीय है।

टैक्स की बाधाएं कम करके ही इनोवेशन को बढ़ावा दे सकेंगे

डॉ. अरुणा शर्मा

देश में टैक्सेशन को 'टैक्स टेररिज्म' कहा जाने लगा है, खासकर इनोवेशन की दुनिया में। प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं कि भारत का भविष्य महज उपभोक्ता-बाजार बनने में नहीं, तकनीकी क्षेत्र का अगुवा बनने में है। सरकार की ओर से आंत्रप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की गई थीं। इससे भारतीय रिसर्चरों को प्रोत्साहन मिला भी, लेकिन सरकारी टैक्स व्यवस्था ने ढेरों नकारात्मक व्यवधान पैदा कर दिए। तीन उदाहरणों से इसे समझें। पहला मामला एंजेल फंड का है। संभावनाओं वाले स्टार्टअप्स को निवेशकों ने यह फंड दिया, लेकिन आयकर विभाग ने इसे स्टार्टअप्स की कमाई मानकर उन्हें नोटिस भेजने शुरू कर दिए। नतीजतन, इनोवेशंस पर ध्यान देने के बजाय छोटे स्टार्टअप्स को अपनी सीमित मैनपॉवर कानूनी मसलों के समाधान में खपानी पड़ गई। दूसरा मामला आईआईटी संस्थानों का है, जिनके पास सीमित रिसर्च फंड होता है। लेकिन समय के साथ उन्होंने उद्योगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग से इंडस्ट्री फंड भी विकसित कर लिए। इन रिसर्च के निष्कर्षों को लागू करने वाले भी तत्काल मिल जाते थे, क्योंकि समस्या की पहचान और जरूरत का आकलन पहले ही किया जा चुका होता था। फिर एक दिन इन प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थानों को जीएसटी के नोटिस मिल गए। इनमें उद्योगों द्वारा वित्तपोषित रिसर्च को सेवा श्रेणी में मान लिया गया। इन दोनों मामलों ने पूरी शोध प्रक्रिया को दो सालों तक बाधित रखा, जब तक कि सरकार ने इन प्रावधानों को वापस नहीं ले लिया। एक दूसरा उदाहरण ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का है, जहां 2023 में 'गेम ऑफ स्किल' (जैसा कि विभिन्न अदालती आदेशों में वर्गीकृत किया गया है) पर जीएसटी 18त्न से बढ़ाकर 28त्न कर दिया गया। यह टैक्स बढ़ोतरी रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से की गई, यानी बढ़ा हुआ टैक्स 2017 से लागू किया गया। इस फैसले से पूरा गेमिंग इनोवेशन ठप हो गया। इनोवेशन महज डीआरडीओ जैसे बड़े संस्थानों में ही नहीं होते, बल्कि ये छोटे स्टार्टअप्स और उनके नवाचार का मिला-जुला परिणाम होते हैं। इन व्यवधानों के चलते भारत ने अपनी बढ़त खो दी। यदि भारत को इनोवेशन का हब बनना है और तकनीकी के क्षेत्र में खुद का सामर्थ्य बढ़ाने पर फोकस करना है तो क्या यह जरूरी नहीं कि इन नई उभरती हुई तकनीकों को टैक्स वसूली के नजरिए से परे रखा जाए? जब देश में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया गया था तो केंद्र और राज्यों ने दीर्घकालिक नीतियां बनाई और कर रियायतें भी दी थीं। क्या अब फिर वो समय नहीं आ गया, जब इस विषय पर समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए? दीर्घकालिक, स्थिर, भरोसेमंद और कन्वर्जेंट पॉलिसी फ्रैमवर्क तैयार किया जाए, ताकि निवेश आकर्षित हो। साथ ही, उन स्टार्टअप्स को भरोसा मिल सके, जो स्थिर नीतियों वाले देशों का रुख कर रहे हैं। यही प्रक्रिया जारी रही तो भारत की छवि एक ऐसे देश की बन जाएगी, जो महज विदेशों में हो रहे इनोवेशन को ही अपनाता है। आज जरूरत है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के करों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। खासकर तब, जबकि हेल्थ, एजुकेशन सेस जैसे उपकर भी लगाए जा रहे हैं। आयकर पर सेस लगाए जाते हैं। यदि इन माध्यमों से लगातार धन एकत्र हो रहा है, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इसका सोशल ऑडिट भी हो। टैक्स से मिलने वाले पैसे को खर्च करते वक्त हमें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि बदले में लोगों को किफायती दामों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। भारत के पास तमाम काबिलियतें हैं। ज्ञान, प्रतिभा की कमी नहीं है। लेकिन जो चीज इस सब पर पानी फेर देती है, वह है रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण का अभाव। यदि हमें विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनना है तो बिना व्यवधान वाले रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। रिसर्चर्स के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वे इन झटकों और प्रशासनिक बदलावों से उबर सकें। इस सबसे उनका ध्यान रिसर्च से भटक जाता है। हमें रिसर्च और इनोवेशन का एक स्थिर इको-सिस्टम बनाना ही होगा।

जजों की संख्या बढ़ाना कितना कारगर

जगदीप सिंह

बीते दिनों संसद ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। यह बदलाव केवल पदों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव लंबित मामलों के निस्तारण पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज लगभग 92,000 मामले लंबित हैं। वर्तमान में सीमित संख्या में जज होने के कारण प्रतिदिन सीमित मामलों की ही सुनवाई हो पाती है। अनेक महत्वपूर्ण अपीलें और याचिकाएं महीनों तक सूचीबद्ध होने की प्रतीक्षा करती रहती हैं। अतिरिक्त चार न्यायाधीशों की नियुक्ति से एक साथ अधिक खंडपीठों का गठन संभव होगा। संविधान पीठों पर भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने का गहरा प्रभाव पड़ेगा। अनेक संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के मामले पांच, सात या नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। न्यायाधीशों की सीमित संख्या के कारण ऐसी पीठें अपेक्षाकृत कम ही गठित हो पाती हैं। अतिरिक्त जज उपलब्ध होने से मुख्य न्यायाधीश नियमित रूप से संविधान पीठों का गठन कर सकेंगे। इससे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर शीघ्र निर्णय आएंगे। परिणामस्वरूप कानूनी स्पष्टता बढ़ेगी और अन्य अदालतों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे। उनसे आने वाले मामलों पर भी इसका प्रभाव होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं। इन न्यायालयों से बड़ी संख्या में अपीलें और विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी होती है तो राज्य स्तर पर भी अनिश्चितता बनी रहती है।अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से इन अपीलों का निस्तारण अधिक तेजी से हो सकेगा। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दायर मामलों में शीघ्र अंतिम फैसला आने से राज्यों में न्यायिक प्रक्रिया भी गति पकड़ेगी। इससे नागरिकों को राज्य स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय प्राप्त करने में लगने वाला कुल समय कम होगा। आम नागरिकों के जीवन पर इसका प्रभाव सबसे अधिक सार्थक होगा। संपत्ति विवाद, पारिवारिक मामले, सेवा संबंधी अपीलें, आपराधिक अपीलें तथा मौलिक अधिकारों से जुड़े मुकदमे अब लंबे इंतजार के बजाय अधिक समयबद्ध तरीके से निपट सकेंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यह बदलाव उनका जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। जो लोग वर्षों से मुकदमेबाजी का खर्च उठाते-उठाते थक चुके हैं, उन्हें राहत मिलेगी। बार-बार अदालत में तारीख पर उपस्थित होने की मजबूरी कम होगी। न्याय अधिक सुलभ, त्वरित और व्यावहारिक प्रतीत होगा। आर्थिक क्षेत्र पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। व्यापारिक विवाद, अनुबंध संबंधी मामले और निवेश से जुड़े मुकदमे लंबे समय तक लंबित रहने से अनिश्चितता बनी रहती है। इसके कारण कंपनियां और उद्यमी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामलों का शीघ्र निस्तारण होने से व्यापारिक वातावरण में सुधार होगा और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। जब लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अधिक गति और दक्षता के साथ कार्य कर रहा है तो न्यायिक व्यवस्था पर उनका विश्वास और मजबूत होगा। साथ ही न्यायाधीशों पर अत्यधिक कार्यभार कम होने से निर्णयों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। हालांकि न्यायाधीशों की संख्या में यह वृद्धि केवल सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उच्च न्यायालयों और जिला स्तर की अदालतों में भी जजों की संख्या बढ़ाने तथा रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता है। यदि उच्च न्यायालय मजबूत होंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक अनावश्यक अपीलें कम पहुंचेंगी। इससे सुप्रीम कोर्ट अपना अधिक समय संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर केंद्रित कर सकेगा। दोनों स्तरों पर एक साथ सुधार होने से ही न्याय व्यवस्था समग्र रूप से अधिक प्रभावी बन सकेगी। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ डिजिटल सुविधाओं का बेहतर उपयोग भी संभव होगा। ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और केस मैनेजमेंट सिस्टम अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे। इससे दूरदराज के राज्यों से आने वाले पक्षकारों और अधिवक्ताओं को भी सुविधा मिलेगी। वैसे केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देने से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा। स्योग्य, अनुभवी और समर्पित न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। इसके साथ ही न्यायालयों के बुनियादी ढांचे और सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना होगा तभी इस वृद्धि का पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा।

मंदिर प्रबंधक तैयार करने का समय

विकास सारस्वत

रामजन्मभूमि मंदिर अपनी प्राण-प्रतिष्ठा के मात्र दो वर्षों के भीतर ही संस्थागत विफलता के एक अप्रत्याशित उदाहरण के रूप में सामने आया है। यहां चढ़ावा चोरी के मामले से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसमें यह बात विशेष रूप से चिंताजनक है कि यह घटना एक ऐसे मंदिर में घटी, जो सैकड़ों वर्षों के कड़े संघर्ष, अनेक लोगों के बलिदान और करोड़ों व्यक्तियों के दान के फलस्वरूप बना है। अयोध्या के अलावा बदरीनाथ धाम-उत्तराखंड और अंबाजी मंदिर-गुजरात के दान-पात्र से भी चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। इतने प्रसिद्ध और संसाधन-संपन्न मंदिरों में गहन निगरानी के बावजूद प्रबंधन की विफलता अन्य मंदिरों में भी चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की आशंकाओं को जन्म देती है। अयोध्या में हुए दुखद घटनाक्रम के बाद एक मुखर प्रतिक्रिया यह आई है कि मंदिरों को कारपोरेट सरीखे पेशेवर तरीके से चलाया जाए। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आइएएस नृपेंद्र मिश्रा ने सीईओ नियुक्ति का सुझाव दिया। उन्होंने इस पदाधिकारी के सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहने की भी अपेक्षा की। हालांकि दोनों ही मत इसकी अनदेखी करते हैं कि मंदिर न तो विशुद्ध रूप से व्यवसाय है और न ही सरकारी उपक्रम। यह अवश्य है कि जवाबदेही में सुधार के लिए दान की गणना में पारदर्शिता, नियमित कार्य

आडिट, विस्तृत नियमावली और खातों की संपूर्ण जांच जैसी कार्यप्रणाली बने। गणना कक्षों में छेड़छाड़-रोधी प्रणाली, सीसीटीवी, आरएफआइडी टैग युक्त दान-पेटियां और बड़े चढ़ावों के लिए ब्लाकचेन जैसी अपरिवर्तनीय लेखा-प्रणाली ऐसा अंकेक्षण मार्ग बना सकती है, जिसे कोई दुर्जन आसानी से धोखा नहीं दे सकता। एक अलग संग्रहालय में ऐसे बहुमूल्य चढ़ावे को सीमित अथवा दीर्घकाल के लिए प्रदर्शित भी किया जा सकता है। तृतीय पक्ष लेखा परीक्षण और सरल भाषा में सारांश सहित विस्तृत लेखा रिपोर्टों को हर तिमाही वेबसाइट पर डालने जैसे बहुत से कदम उठाए जा सकते हैं, जो दानदाताओं एवं श्रद्धालुओं में विश्वास का भाव बनाएं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और गुरुवायुर जैसे कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्था बनी भी हुई है। यह भी स्मरण रहे कि मंदिर न तो कोई ऐसी कंपनी है जो शेयरधारकों के लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करे और न ही वह शासकीय दायित्व का भाग है, जो सरकार के जनकल्याण उद्देश्यों की पूर्ति करे। मंदिर एक जीवंत धार्मिक संस्था है, जिसकी वैधता उतनी ही मात्रा में अनुष्ठानिक शुद्धता, परंपरा और पवित्रता पर टिकी है, जितनी आर्थिक शुचिता पर। अत: कारपोरेट प्रबंधन को ज्यों का त्यों मंदिरों पर थोपने के बजाय एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जो आडिट, प्रौद्योगिकी, आंतरिक नियंत्रण, पेशेवर वित्त प्रबंधन जैसे आधुनिक प्रशासकीय उपकरणों को आगम शास्त्र और धार्मिक व्यवस्था के अधीन रखे। मंदिर के अपने अनुष्ठानों पर अधिकार का स्रोत आगम शास्त्र यानी परंपराएं हैं। वे ऐसे संहिताबद्ध शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो विभिन्न संप्रदायों के मंदिरों के लिए भिन्न प्रकार के प्रविधान निश्चित करते हैं। जैसे वैष्णव मंदिरों के लिए पाञ्चरात्र और वैखानस आगम, शैव मंदिरों के लिए कामिक, करण और भैरव आगम और शाक्त संप्रदायों के लिए शक्ति आगम। ये कोई आंतरिक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाएं' यानी एसओपी नहीं हैं, जो प्रबंधन की दक्षता को निरूपित करें, बल्कि ये मंदिर का अपना संवैधानिक कानून हैं। यदि किसी सीईओ को धर्मशास्त्रीय प्रशिक्षण के बिना मंदिर संचालन का अधिकार दिया जाए, तो वह भली मंशा के बावजूद प्रतिष्ठित इष्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। वह ऐसे परिवर्तन कर सकता है, जो स्वयं देवता की प्राण-प्रतिष्ठा की पवित्रता को निरस्त कर दे। कुछ इसी प्रकार का दोष सरकारी बोर्डों के मत्थे लगता है, जो परंपराओं की विशिष्टताओं के विपरीत विभिन्न मंदिरों पर एक समान मंदिर-प्रबंधन नियम थोप इस विविधता को रौंद देते हैं। आगमिक मंदिरों में ऐतिहासिक रूप से सत्ता का एक अंतर्निहित पृथक्करण रहा है। केवल अर्चक या पुजारी ही पूजा-अनुष्ठान कर सकता है। मंदिर वास्तु-संरक्षक, मंदिर की संरचना एवं उसकी शिल्प शास्त्रीय अनुरूपता सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार लौकिक ट्रस्टी जो कभी राजा होते थे, मंदिर के भौतिक रखरखाव, भूमि, कोष, सुरक्षा एवं विवाद निस्तारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह विखंडन आध्यात्मिक और भौतिक सत्ताओं को एक ही शक्ति में केंद्रित होने से रोकता था, पर एक सर्वशक्तिमान सीईओ पुन: ऐसे त्रुटिपूर्ण केंद्रीकरण को जन्म दे सकता है। अल्पकालिक अवधि में ऐसे ट्रस्टियों का चयन जो आधुनिक प्रबंधन के साथ आगम शास्त्रों के भी ज्ञाता हों, थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। वर्तमान परिस्थितियों का उपयोग एक ऐसे अवसर के रूप में किया जा सकता है, जो बिजनेस मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट की शैली पर टैंपल मैनेजमेंट यानी मंदिर-प्रबंधन के लिए कार्यकारी तैयार करे। तिरुपति या अयोध्या जैसे बड़े मंदिर ऐसे संस्थान खड़े करने का बीड़ा उठा सकते हैं। इन संस्थाओं का उद्देश्य ऐसे मंदिर प्रबंधकों का विकास होना चाहिए, जिनमें आध्यात्मिक संवेदनशीलता के साथ आधुनिक प्रबंधन की कुशलताएं हों। अर्चकों के लिए चर्या पाद, परिचारकों और स्थानिकों के क्रिया पाद, अध्येताओं एवं कलाकारों के लिए ज्ञान पाद व सभी के लिए योग पाद की अनिवार्यता वैसी आचरण संहिता हैं, जो प्रबंधन और मानव संसाधन को व्यावहारिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित कर सकती हैं। अयोध्या में हुई चोरी धर्म की विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्थापन की विफलता है। इसलिए समाधान यह नहीं होना चाहिए कि मंदिर का कारपोरेट अधिग्रहण हो। न ही यह कि परंपरा के नाम पर मंदिरों की विशाल भौतिक संपत्ति को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। समाधान वह है, जिसका आदर्श स्वयं आगमों ने सदियों पहले प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक सत्ता को भौतिक प्रशासन से पृथक रखा जाए और प्रशासन को इस प्रकार उत्तरदायी बनाया जाए।

हर मोर्चे पर नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान पर हमले की पूरी तैयारी है। उसी संदेश में उन्होंने हमला टालने की भी बात कही। इसका कारण यह बताया गया कि ईरान और कई खाड़ी देशों ने इसके लिए आग्रह किया है, क्योंकि समझौते की रूपरेखा बन चुकी है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद ईरानी सैन्य सूत्रों के हवाले से खबर आई कि होर्मुज जलमार्ग को खोलने पर कोई सहमति बनी ही नहीं है। इससे कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस ने हमास के निरस्त्रीकरण का भी पंद्रह सूत्रीय ढांचा घोषित किया था, जबकि उसी दिन अमेरिकी सेंट्रल कमान ने ईरान पर भारी बमबारी कर दी।

रामिश सिद्दीकी

कुछ ही दिनों के अंतराल में अमेरिकी सरकार की ये चार घोषणाएं एक गंभीर नीतिगत संकट का संकेत देती हैं। व्यापार हो, गठबंधन हो, महाशक्तियों से संवाद हो या युद्ध-लगभग हर मोर्चे पर अमेरिकी सरकार द्वारा पहले घोषणा की गई और उसे लागू करने वाली व्यवस्था बाद में सामने आई। कई मामलों में तो ऐसी व्यवस्था बन ही नहीं सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही दुनिया को यह संदेश दिया था कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध को शीघ्र समाप्त करवा देंगे, लेकिन उस घोषणा को भी कई महीने बीत चुके हैं और आज वह युद्ध पहले से अधिक तीव्र हो गया है। जिस युद्ध को समाप्त करने का वादा किया गया था, वह नहीं रुका और जिसकी चर्चा भी नहीं थी, वह ईरान युद्ध शुरू हो गया। ट्रंप के मनमाने फैसलों की कीमत वे देश चुका रहे हैं, जिनसे उन्होंने पूछा तक नहीं। दरअसल वाशिंगटन तक पहुंचने में असमर्थ ईरान अब उन्हीं देशों को निशाना बना रहा है, जो उसकी पहुंच में हैं।

खाड़ी के छह देश ईरान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। ऊर्जा प्रतिष्ठान और खारे जल के शोधन संयंत्र तक निशाने पर आ चुके हैं। होर्मुज जलमार्ग बंद हो चुका है। इसके कारण ईरान का युद्ध अब केवल क्षेत्रीय नहीं रह गया है। पहले होर्मुज जलमार्ग से प्रतिदिन लगभग 88 जहाज गुजरते थे, जबकि जुलाई में यह संख्या घटकर मात्र 10 रह गई। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड अब जहाजों की आवाजाही पर शुल्क वसूलने पर आमादा है-प्रति जहाज 20 लाख डालर तक, वह भी युआन, बिटकाइन या अन्य मुद्राओं में। इससे कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हीं जहाजों को सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन माल के मूल्य का 20 प्रतिशत शुल्क लेकर। इस प्रकार एक ही जलमार्ग पर दो 'चुंगी नाके' बन गए हैं और दोनों उन्हीं सरकारों के हैं, जिन्होंने उसे बंद कराया है।

दुनिया का लगभग एक-चौथाई समुद्री तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसलिए इसका बोझ केवल खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। इसका प्रभाव यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका-हर महाद्वीप में बीमा, माल-भाड़े और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के रूप में दिखाई दिया है। सबसे अधिक बोझ उन्हीं खाड़ी देशों पर पड़ा है, जो इस जलमार्ग के दोनों किनारों पर बसे हैं। यह स्थिति किसी देश की जनता ने नहीं चुनी, लेकिन इसकी कीमत हर देश की जनता चुका रही है। होर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोलने के सभी प्रयास अब तक विफल होते दिखाई दे रहे हैं। अब फलस्तीन शांति बोर्ड को इसी पृष्ठभूमि में देखिए। वह सफल होगा या नहीं, यह कहना कठिन है, क्योंकि पांच महीनों में उससे केवल एक बैठक, कुछ वादे और ऐसा ढांचा सामने आया है, जिसकी लगभग प्रत्येक शर्त अधूरी प्रतीत होती है। फरवरी में जिस स्थिरीकरण बल (स्टेबिलाइजेशन फोर्स) की तैनाती का वचन दिया गया था, वह आज तक तैनात नहीं हो सका। गाजा का प्रशासन संभालने के लिए गठित फलस्तीनी समिति भी अब तक वहां प्रवेश नहीं कर सकी है। दरअसल शांति बोर्ड का ढांचा उसी सबसे बड़ी गुत्थी को अनछुआ छोड़ देता है। इजरायल का कहना है कि वास्तविक निरस्त्रीकरण से पहले उसकी वापसी संभव नहीं है, जबकि हमास का तर्क है कि इजरायली वापसी से पहले निरस्त्रीकरण नहीं हो सकता। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए 14 दिन का समय निर्धारित किया गया है। विडंबना यह भी है कि इस शांति बोर्ड का अध्यक्ष स्वयं अमेरिका है, जो इस समय ईरान के साथ युद्धरत है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार खाड़ी क्षेत्र के देशों के आग्रह पर उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकी है। पिछले पांच महीनों में यह दूसरी बार है, जब खाड़ी के प्रमुख देशों ने ईरान-अमेरिका संघर्ष को बड़े युद्ध का रूप लेने से रोका है। इसके बावजूद किसी स्थायी समझौते की संभावना अभी दूर दिखाई देती है। ट्रंप का कहना है कि प्रस्तावित सहमति होर्मुज जलमार्ग को स्थायी रूप से खुला रखेगी, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी व्यवस्था में इस जलमार्ग पर उसकी संप्रभुता बनी रहेगी। ये किसी एक समझौते की दो अलग-अलग व्याख्याएं नहीं, बल्कि दो भिन्न समझौते प्रतीत होते हैं।

जून में शांति को लेकर दोनों देशों के बीच बनी सहमति भी इसी व्याख्यात्मक मतभेद के कारण टूट गई थी। ट्रंप सरकार की अब तक की घोषणाओं ने दुनिया को होर्मुज जलमार्ग पर गतिरोध, यूरोप में जारी युद्ध और गाजा में अधूरी शांति दी है। सवाल यह नहीं है कि वाशिंगटन एक और घोषणा कर सकता है या नहीं, बल्कि वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या वह अपनी किसी भी घोषणा को उसके तार्किक और व्यावहारिक परिणाम तक पहुंचा पाएगा या नहीं।

सीएम हेल्पलाइन 1076 के प्रभावी संचालन एवं शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर प्रदेश स्तरीय वर्चुअल प्रशिक्षण सम्पन्न

समयबद्ध, पारदर्शी एवं समाधान आधारित शिकायत निवारण पर अधिकारियों को दिए गए विस्तृत दिशा-निर्देश

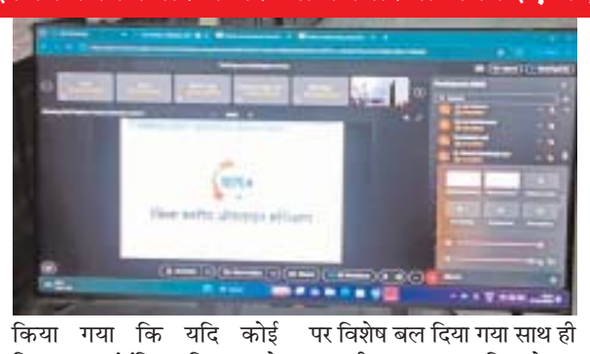

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के प्रभावी संचालन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण तथा पोर्टल के बेहतर उपयोग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, विभागीय नोडल अधिकारी तथा शिकायतों के निराकरण से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण में शामिल हुए प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर अंशुल वर्मा, राकेश गोलछा एवं अनुराग दीवान ने किया उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के नवीन प्रावधानों, स्तरवार शिकायत निराकरण, समय-सीमा के पालन, विभागीय समन्वय शिकायत स्थानांतरण स्पेशल क्लोजर, पोर्टल संचालन तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 राज्य शासन की महत्वपूर्ण जन शिकायत निवारण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं सीधे शासन तक पहुंचा सकते हैं अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि शिकायतों का उद्देश्य केवल पोर्टल पर जवाब दर्ज करना नहीं बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है इसके लिए आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण, तथ्यात्मक जांच, समाधान के बाद कार्रवाई का विवरण, संबंधित दस्तावेज एवं फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है एल-1 से एल-4 तक समझाई गई शिकायत निराकरण की प्रक्रिया प्रशिक्षण में शिकायतों के स्तरवार निराकरण की पूरी प्रक्रिया समझाई गई बताया गया कि एल-1 स्तर पर विभागीय अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में शिकायत का परीक्षण एवं निराकरण करेंगे समय पर समाधान नहीं होने अथवा संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में शिकायत क्रमशः एल-2, एल-3 एवं एल-4 स्तर तक पहुंचती है, जहां वरिष्ठ अधिकारी प्रकरण की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेते हैं। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई शिकायत संबंधित विभाग से जुड़ी नहीं है तो उसे लंबित रखने के बजाय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से तत्काल संबंधित विभाग को स्थानांतरित किया जाए, जिससे अनावश्यक विलंब न हो और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सके गुणवत्तापूर्ण निराकरण एवं स्पेशल क्लोजर पर विशेष जोर प्रशिक्षण के दौरान शिकायतकर्ता से नियमित संवाद बनाए रखने, आवश्यकता पड़ने पर स्थल निरीक्षण करने तथा समाधान की जानकारी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया साथ ही यह भी बताया गया कि स्पेशल क्लोजर केवल विशेष परिस्थितियों, जैसे न्यायालय में लंबित प्रकरण, शासन की नीति से जुड़े विषय अथवा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के दायरे से बाहर के मामलों में ही नियमानुसार किया जाएगा पोर्टल संचालन का कराया गया लाइव प्रदर्शन मास्टर ट्रेनरों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल का लाइव प्रदर्शन करते हुए नई शिकायत प्राप्त करने, जांच अधिकारी नियुक्त करने, कार्रवाई दर्ज करने, दस्तावेज एवं फोटो अपलोड करने, शिकायत स्थानांतरित करने, समय-सीमा की निगरानी करने तथा अंतिम निराकरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। साथ ही डैशबोर्ड के माध्यम से विभागवार प्रदर्शन, लंबित एवं निराकृत शिकायतों की समीक्षा और समय-सीमा विश्लेषण की जानकारी भी साझा की गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विभाग प्रतिदिन लंबित शिकायतों की समीक्षा कर समय-सीमा समाप्त होने से पूर्व उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करे प्रशिक्षण के अंत में बताया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के संचालन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर जिले के ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक से संपर्क कर आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है, ताकि शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया निर्बाध एवं प्रभावी बनी रहे।

जिले में अब तक 505.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज, चिरमिरी में सर्वाधिक बारिश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में इस वर्ष मानसून सक्रिय बना हुआ है जिले में 1 जून से 7 अगस्त 2026 तक कुल 505.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की विभिन्न तहसीलों में वर्षा का आंकड़ा संतोषजनक रहा है जिससे किसानों को खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिल रही है जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में **सर्वाधिक वर्षा 672.2 मिलीमीटर चिरमिरी तहसील में दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम 391.2 मिलीमीटर वर्षा केल्हारी तहसील में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ तहसील में 639.4 मिमी खड़गवां में 462.0 मिमी भरतपुर में 477.0 मिमी तथा कोटाडोल में 391.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है प्रशासन के अनुसार मानसून की नियमित गतिविधियों के चलते जिले के अधिकांश क्षेत्रों में जलस्तर में सुधार हुआ है तालाबों, जलाशयों एवं अन्य जल स्रोतों में भी पानी की उपलब्धता बढ़ी है जिससे पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था को लाभ मिलने की संभावना है वहीं कृषि कार्य भी तेजी से जारी हैं और किसान धान सहित अन्य खरीफ फसलों की खेती में जुटे हुए हैं जिला प्रशासन लगातार वर्षा की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। संबंधित विभागों को आवश्यक सतर्कता बरतने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि लगातार बारिश के दौरान नदी-नालों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें तथा मौसम संबंधी जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें जले में अब तक दर्ज हुई औसत वर्षा मानसून की अच्छी प्रगति का संकेत मानी जा रही है और आने वाले दिनों में वर्षा का सिलसिला जारी रहने की संभावना के बीच प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति की निगरानी कर रहा है।

14 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा भारत विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार आगामी 14 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ में भारत विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा इस संबंध में राज्य शासन के संस्कृति विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं दिवस का उद्देश्य देश के विभाजन की त्रासदी से नई पीढ़ी को परिचित कराना विभाजन से प्रभावित लाखों लोगों के संघर्ष, साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देना तथा राष्ट्रीय एकता अखंडता और सामाजिक सद्भाव की भावना को मजबूत करना है निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में भारत विभाजन पर आधारित विशेष प्रदर्शनी व्याख्यान परिचर्चा एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा जाएगा साथ ही मतुआ समुदाय के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर आधारित लघु वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया जाएगा विभाजन पीड़ितों की स्मृति में कैंडल मार्च तथा विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा संस्कृति विभाग ने 1 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक MyGov पोर्टल पर आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतियोगिता में अधिक से अधिक युवाओं एवं विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं राज्य स्तर पर भी राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा इसके साथ ही हर घर तिरंगा एवं वंदे मातरम् अभियान के प्रभावी संचालन के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी तिरंगा यात्रा रैली, मेला, प्रतिज्ञा, सेल्फी अभियान, मैराथन और सामूहिक वंदे मातरम् गायन जैसे कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग होगी आयोजन से संबंधित फोटो एवं वीडियो निर्धारित ई-मेल और पोर्टल के माध्यम से संस्कृति विभाग को भेजे जाएंगे।

व्हाट्सएप हैक कर ठेकेदार से 1.30 लाख की ठगी पीडब्ल्यूडी के पूर्व एसडीओ बनकर मांगे रुपए

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी में साइबर ठगों ने पीडब्ल्यूडी के सेवानिवृत्त एसडीओ का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर एक ठेकेदार से 1 लाख 30 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। आरोपियों ने यूपीआई बंद होने का झांसा देकर परिचित होने का फायदा उठाया और अलग-अलग किश्तों में रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है पोहरी की अंसारी कॉलोनी निवासी ठेकेदार उदय सिंह धाकड़ (39) ने पुलिस को बताया कि 28 जुलाई को उनके मोबाइल पर पीडब्ल्यूडी के पूर्व एसडीओ हरिवल्लभ वर्मा के नाम से व्हाट्सएप संदेश आया मैसेज में नेटवर्क समस्या और यूपीआई ब्लॉक होने की बात कहकर एक बारकोड भेजा गया तथा तत्काल एक लाख रुपए की मदद मांगी गई परिचित का संदेश समझकर ठेकेदार ने पहले 40 हजार फिर 30-30 हजार रुपए बारकोड के माध्यम से भेज दिए बाद में बारकोड की लिमिट समाप्त होने का हवाला देकर एक मोबाइल नंबर पर 30 हजार रुपए और ट्रांसफर करा लिए गए इस तरह कुल 1.30 लाख रुपए की ठगी हो गई कुछ देर बाद परिचितों से व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने तुरंत साइबर सेल और पोहरी थाने में शिकायत दर्ज कराई पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत प्रकरण दर्ज कर बैंक खातों मोबाइल नंबर और डिजिटल ट्रांजेक्शन की जांच शुरू कर दी है विभागीय अधिकारियों के अनुसार हरिवल्लभ वर्मा करीब एक माह पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की पुष्टि भी सामने आई है।

रचा इतिहास: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में लक्ष्य हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बना

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के नेतृत्व में एमसीबी ने 95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य में दर्ज की ऐतिहासिक उपलब्धि

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभावी नेतृत्व में जिले ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है इस उपलब्धि के साथ एमसीबी छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है जिसने इस चुनौतीपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया है इस उपलब्धि के पीछे सुनियोजित रणनीति गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समयबद्ध उपचार और स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम का सतत प्रयास रहा जिले में एचआईवी कार्यक्रम का प्रभावी संचालन जिला नोडल अधिकारी डॉ. मो. वसीक अस्दक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक शिशिर जायसवाल के कुशल निर्देशन में किया गया, जिनके नेतृत्व में मैदानी स्तर पर अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया 95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन एचआईवी संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95-95-95 लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एमसीबी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की 95 (पहचान एवं जांच संभावित एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की समय पर पहचान एवं जांच कर जिले ने पहला 95 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया द्वितीय 95 (उपचार) : संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) से जोड़कर दूसरा 95 प्रतिशत लक्ष्य भी सफलतापूर्वक हासिल किया तृतीय चरण (वायरल लोड सप्रेशन) संक्रमित मरीजों के शरीर में वायरस की सक्रियता को न्यूनतम स्तर पर लाने के 99 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले जिले ने 98 प्रतिशत वायरल लोड सप्रेशन प्राप्त कर असाधारण प्रदर्शन किया जो राष्ट्रीय मानकों के अत्यंत निकट है आईसीटीसी काउंसलरों की रही महत्वपूर्ण भूमिका इस सफलता में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर के काउंसलरों का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा। निशा सिंह एवं विजेंद्र खटकर ने मरीजों की प्रभावी काउंसलिंग, नियमित फॉलोअप तथा उपचार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समर्पण और संवेदनशील कार्यशैली ने मरीजों का विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पहली बार नैनो डीएपी अपनाकर वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़े किसान राजमन सिंह

ग्राम जरौधा के किसान ने आधुनिक उर्वरक को अपनाया बेहतर उत्पादन और कम लागत की जताई उम्मीद

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है इसका सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के विकासखंड खड़गवां अंतर्गत ग्राम जरौधा के किसान राजमन सिंह ने इस खरीफ सीजन में पहली बार अपनी फसल में नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। उनका मानना है कि आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है राजमन सिंह ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से अपनी आवश्यकता अनुसार नैनो डीएपी प्राप्त किया उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनके गांव तथा आसपास के कई किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग किया था, जिसके परिणाम काफी उत्साहजनक रहे। फसलों की अच्छी बढ़वार और बेहतर उत्पादन को देखकर उनके मन में भी इस आधुनिक उर्वरक के प्रति विश्वास बढ़ा और उन्होंने इस वर्ष स्वयं इसका उपयोग करने का निर्णय लिया राजमन सिंह ने कहा मैं पहली बार नैनो डीएपी का उपयोग कर रहा हूं पिछले साल आसपास के किसानों को इसके अच्छे परिणाम मिले थेउनकी फसल देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली मुझे विश्वास है कि इसके उपयोग से मेरी फसल की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी उन्होंने बताया कि नैनो डीएपी का एक बड़ा लाभ इसकी आसान परिवहन व्यवस्था भी है पहले पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियां ढोनी पड़ती थीं जबकि नैनो डीएपी की छोटी बोतल को आसानी से बैग में रखकर घर लाया जा सकता है इससे समय श्रम और परिवहन की लागत तीनों में बचत होती है राजमन सिंह ने अन्य किसानों से भी नई कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यदि वैज्ञानिक सलाह के अनुसार आधुनिक उर्वरकों का सही उपयोग किया जाए तो खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है कृषि विभाग द्वारा जिले में किसानों को नैनो डीएपी सहित आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के संबंध में लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा है विभाग का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रेरित करना,उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना तथा कम लागत में अधिक उत्पादन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है जिले में बढ़ती किसान भागीदारी यह दर्शाती है कि आधुनिक तकनीकों के प्रति किसानों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है और वे वैज्ञानिक खेती की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

15 अगस्त को जिलेभर में लगेगी उल्लास महा-चौपाल जनभागीदारी से साक्षरता अभियान को मिलेगा विस्तार

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लास महा-चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य समाज में शिक्षा और साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा असाक्षर लोगों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है जिला प्रशासन के अनुसार, यह आयोजन साक्षरता को जन-अभियान का स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि शिक्षक विद्यार्थी, स्वयंसेवक महिला स्व-सहायता समूह और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रहेगी गांव-गांव और घर-घर तक शिक्षा का संदेश पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी महा-चौपाल के दौरान शिक्षा के महत्व पर संवाद उल्लास शपथ साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम परिचर्चा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैली पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा साथ ही नवसाक्षरों और अभियान में योगदान देने वाले स्वयंसेवकों का सम्मान भी किया जाएगा कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को विशेष रूप से प्रेरित किया जाएगा जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए हैं ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने प्रबुद्ध नागरिकों और स्वयंसेवकों से भी इस अभियान में सहयोग कर शिक्षा की अलख जगाने की अपील की है।

पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश: क्रीड़ा परिसर लालपुर में लायंस क्लब और ग्रीन वैली क्लब ने किया वृहद वृक्षारोपण

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने और प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनेन्द्रगढ़ के लालपुर स्थित क्रीड़ा परिसर में लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ एवं ग्रीन वैली क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रेरणादायी आयोजन में क्रीड़ा परिसर के खिलाड़ियों, छात्र-छात्राओं, प्रशिक्षकों तथा क्लब के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया कार्यक्रम के दौरान क्रीड़ा परिसर के खेल मैदान एवं आसपास के क्षेत्र में फलदार छायादार तथा औषधीय पौधों का रोपण किया गया। छात्र-छात्राओं ने अपनी माताओं के सम्मान में पौधे लगाकर उन्हें प्रकृति से जोड़ने का भावनात्मक संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधारोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण और नियमित देखभाल का भी संकल्प लिया इस अवसर पर लायंस क्लब एवं ग्रीन वैली क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है बल्कि यह मातृत्व के सम्मान पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संदेश देने वाला अभियान है उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो धरती को पुनः हरा भरा बनाया जा सकता है ग्रीन वैली क्लब के कौशल अग्रवाल ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष पृथ्वी के जीवन का आधार हैं। उन्होंने सभी से अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया विनोद जायसवाल ने कहा कि पौधारोपण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और नियमित देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है प्रत्येक नागरिक को अधिक से अधिक लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए तभी इस अभियान का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा रामचरित द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और गर्मी के दिनों में शीतल छाया देकर जीवन को सहज बनाते हैं उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रकृति हमारे बिना तो जीवित रह सकती है लेकिन प्रकृति के बिना मानव जीवन एक दिन भी संभव नहीं है इसलिए पर्यावरण संरक्षण हम सभी का नैतिक दायित्व है कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं खिलाड़ियों प्रशिक्षकों अधिकारियों एवं क्लब सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई।

भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका: चुनाव याचिका खारिज नहीं होगी, हाईकोर्ट में मेरिट पर चलेगी सुनवाई

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पाटन विधायक भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव याचिका के ट्रायल के दौरान भूपेश बघेल अपने सभी कानूनी और तथ्यात्मक तर्क हाईकोर्ट के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र होंगे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की यह चुनाव याचिका भाजपा नेता एवं दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से 48 घंटे पहले लागू साइलेंस पीरियड में भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र में रोड शो और चुनावी गतिविधियां संचालित कर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन किया सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यदि आरोपों को सही भी मान लिया जाए, तब भी यह केवल धारा 126 के तहत चुनावी अपराध हो सकता है न कि धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण उन्होंने यह भी कहा कि कथित रोड शो का चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भूपेश बघेल लगभग 20 हजार मतों के अंतर से चुनाव जीते थे सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि रोड शो में सीमित संख्या में लोग शामिल थे और मुख्यमंत्री होने के कारण उनकी सुरक्षा व्यवस्था स्वाभाविक थी इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि कथित उल्लंघन का चुनाव परिणाम पर प्रभाव पड़ा या नहीं यह तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसका निर्णय साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई हाईकोर्ट में होगी गौरतलब है कि विजय बघेल ने वर्ष 2024 में दायर चुनाव याचिका में भूपेश बघेल की विधायकी को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि मतदान से पहले प्रचार प्रतिबंध अवधि के दौरान उन्होंने समर्थकों के साथ रैली एवं रोड शो निकालकर वोट मांगे जो चुनाव कानून का उल्लंघन है।

पचमढ़ी में आर्मी अधिकारी और जेन-जी से साइबर फ्रॉड, बिजली बिल बकाया का भेजा मैसेज, लिंक ओपन करते ही कटे रुपए

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में पचमढ़ी आर्मी अधिकारी और एक जेन-जी (कॉलेज स्टूडेंट) साइबर फ्रॉड का शिकार हुए। ठग ने बिजली का बकाया बिल का मैसेज भेजकर यह शिकार किया। जिसमें हजारों रुपए खाते से कुछ सेकंड में उड़ गए। जानकारी के मुताबिक फरियादी सेना शिक्षा केंद्र (ACE) आर्मी सेंटर ऑफ एजुकेशन, पचमढ़ी में ऑफिसर है। जिन्हें 30 जुलाई को मोबाइल पर मैसेज आया। जिसमें बिजली बिल बकाया लिखा था। जबकि उनका बिजली का कोई बिल पेंडिंग नहीं था। उस मैसेज में लिखे नम्बर पर उन्होंने कॉल कर बिल पेंडिंग नहीं होने की बात बताई। लिंक क्लिक करते ही वेड्रॉल हुआ कॉलर ने उन्हें बोला कि एक लिंक आएगी, जिसमें आप अपडेट कर देना कि बिल का पेमेंट हो गया है। आर्मी ऑफिसर ने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया, खाते से रुपए वेड्रॉल होने के मैसेज आ गया। उन्होंने तुरंत बैंक और पुलिस थाने में इसकी शिकायत की। साइबर सेल में जांच के बाद पचमढ़ी थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

माखननगर में स्टूडेंट से भी ठगी: इसी प्रकार माखननगर थाने में भी एक कॉलेज स्टूडेंट ने साइबर ठगी की शिकायत की। फरियादी ने बताया कि 2 अगस्त को शाम को अचानक से उसका मोबाइल हैक हो गया। कुछ देर बाद जब मोबाइल को रिस्टार्ट कर चालू किया तो सारी एप डिलीट हो गई। फोन पे को इंस्टॉल कर बैंक बैलेंस चैक किया तो 46हजार रुपए निकल चुके थे। साइबर ठगी के लगातार मामले सामने आ रहे है। जिसमें स्टूडेंट्स, बुजुर्ग, सरकारी अधिकारी, किसान सभी अन्य वर्गों के लोग भी ठगी का शिकार हो रहे। पुलिस द्वारा साइबर अपराधों को रोकने के लिए नाटक, स्लोगन, अन्य प्रकार से जागरूक अभियान चला रही। बावजूद साइबर अनेकों प्रकार से लोगों को ठग रहे। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक में जिलेभर के थानों में 12 से ज्यादा साइबर फ्रॉड के अपराध दर्ज हो चुके है। जिसमें करीब 5 लाख से ज्यादा रुपए लोगों के खाते से साइबर ठग निकाल चुके हैं।

घरेलू विवाद के चलते बिजली के पोल पर लटका मिला शव

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। देवनगर थाना क्षेत्र में जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद का दुखद अंत हो गया। बुधवार शाम 34 साल के युवक का शव गांव के पास करीब 60 फीट ऊंचे बिजली के पोल पर लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव नीचे उतारा। शव को जिला अस्पताल भेजा गया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी हरिओम आस्तया ने बताया कि मृतक की पहचान कल्याण सिंह अहिरवार, पिता हल्केराम अहिरवार, उम्र 34 साल के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि परिवार की जमीन बेचने के बाद मिली राशि के बंटवारे को लेकर उसका पिता से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि पिता ने पूरी राशि बड़े बेटे को दे दी थी। कल्याण सिंह अपने हिस्से की मांग कर रहा था। पुलिस के मुताबिक विवाद के बाद कल्याण सिंह घर से निकलते समय परिजनों से कहकर गया था कि वह फांसी लगा लेगा। कुछ देर बाद उसका शव बिजली के पोल पर मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी हरिओम आस्तया ने कहा कि शुरुआती जांच में जमीन बेचने के बाद मिले पैसों के बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है।

रतलाम में रात को आम आदमी बने कलेक्टर

बिना सरकारी गाड़ी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, एक घंटे तक वार्डों में घूमकर परखी व्यवस्थाएं

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया गुरुवार रात आम व्यक्ति की तरफ मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वह भी बिना सरकारी गाड़ी और सुरक्षा गार्ड के। बिना जानकारी दिए कलेक्टर एसडीएम तरुण जैन को साथ लेकर खुद प्राइवेट कार चलाकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। कलेक्टर एक घंटे तक मेडिकल कॉलेज के वार्डों से लेकर विभागों में घूमे।

कलेक्टर कटेसरिया ने 4 अगस्त को रतलाम में पदभार ग्रहण किया है। वर्तमान में वह सर्किट हाउस में रुके है। गुरुवार रात एसडीएम को बुलाया। एसडीएम को बिना बताए कार में बैठाकर खुद कार चलाकर रात 9 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। कलेक्टर रात 10 बजे तक मेडिकल कॉलेज के अलग-अलग विभाग में घूमे। लेकिन मेडिकल कॉलेज की डीन व डॉक्टरों को इसकी जानकारी नहीं लग पाई।

आम व्यक्ति की तरह ली जानकारी: कलेक्टर ने भर्ती मरीजों की जानकारी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ नर्सों से आम व्यक्ति की तरह ली। स्टाफ को भी पता नहीं चल पाया कि लोअर, टी-शर्ट में यह कलेक्टर है। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से भर्ती मरीजों के इलाज के बारे में भी जाना। कलेक्टर ने भर्ती मरीजों के वार्डों में जाकर देखा। नर्सों से आम व्यक्ति की तरह पूछा कि सर्दी खांसी के मरीजों की सामान्य जानकारी ली। पूछा कि मरीजों को किस प्रकार समस्या आती है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर का बिना बताए जाने के पीछे मेडिकल कॉलेज में आए मरीजों से किस तरह की समस्या आती है, स्टाफ का व्यवहार कैसा रहता है जानने के लिए कलेक्टर पहुंचे थे।

अलग-अलग वार्डों को देखा

कलेक्टर ने एसडीएम के साथ नेत्र रोग वार्ड, बाल्य एवं शिशु रोग वार्ड समेत कई वार्डों में चुपचाप जाकर देखा। सबसे बड़ी बात यह रही कि कलेक्टर 1 घंटे तक मेडिकल कॉलेज में घूमे। लेकिन कॉलेज की डीन डॉ. अनिता मूथा से लेकर डॉक्टरों को कलेक्टर की भनक तक नहीं लग पाई। इसके एक दिन पहले बुधवार रात भी कलेक्टर शहर में निकल गए थे। दो बत्ती क्षेत्र में एक सामान्य व्यक्ति की तरह चाट दुकान पर पहुंच चाट खाई थी।

भोपाल से ट्रांसफर होकर आए

कलेक्टर कटेसरिया रतलाम आने के पहले मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव तथा कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल के संचालक के पद पर पदस्थ थे। इसके पहले वह सतना जिले में कलेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

बुरहानपुर में दो दिन नहीं होगी जलापूर्ति, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट 48 घंटे बंद, बाढ़ के बाद सफाई, पानी संग्रह की अपील

मीडिया ऑडीटर, बुरहानपुर (निप्र)। बुरहानपुर शहर में 8 और 9 अगस्त को दो दिनों तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी और जलावर्धन योजना प्रबंधन विभाग द्वारा बसाड़ स्थित जल शोधन संयंत्र (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट) में रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न होगी। विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, शनिवार 8 अगस्त और रविवार 9 अगस्त को संयंत्र में आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा। इसमें सीएलएफ क्लैरिफ्लोक्युलेटर की सफाई भी शामिल है। इस अवधि में संयंत्र 48 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रहेगा, जिससे शहर की जलापूर्ति प्रभावित होगी। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने नागरिकों से अपील की कि वे इन दो दिनों के लिए आवश्यकतानुसार जल का संग्रहण कर लें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद नियमित जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

अधिकांश क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित होगी: हालांकि, नगर निगम द्वारा उतावली संपवेल की पुरानी व्यवस्था से कुछ क्षेत्रों में जल वितरण जारी रहेगा। लेकिन, इस व्यवस्था से पूरे शहर में पानी की आपूर्ति संभव नहीं हो पाएगी, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रखरखाव और सफाई कार्य हाल ही में ताप्ती नदी में आई बाढ़ के कारण पानी में मिट्टी की मात्रा बढ़ जाने के कारण आवश्यक हो गया है।

अगस्त और सितम्बर की राशन सामग्री एकमुश्त की जाएगी वितरित

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. द्वारा जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त एवं सितम्बर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा है कि राशन सामग्री का शत् प्रतिशत उठाव 15 अगस्त तक पूरा कर उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण सुनिश्चित किया जाए। अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों को 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार राशन (गेहूँ, चावल) एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी में आने वाले हितग्राहियों को 5 कि.ग्रा. प्रति सदस्य राशन दिया जाता है। साथ ही दोनों श्रेणी के हितग्राहियों को एक कि.ग्रा. नमक प्रति परिवार दिया जाता है। पीओएस मशीन में अगस्त एवं सितम्बर की राशन सामग्री को वितरित करते समय दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा पर राज्यस्तरीय कार्यशाला की तैयारी तेज, निजी विश्वविद्यालयों ने बनाई रणनीति

मीडिया ऑडीटर, भोपाल, (निप्र)। भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग और मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय संघ ने तैयारियां तेज कर दी हैं गुरुवार को मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग के चेयरमैन डॉ. खेमचंद डेहरिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों की सहभागिता से भोपाल के पूर्व विधानसभा स्थित मिंटो हॉल में आयोजित होने वाली दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला की विस्तृत रणनीति तैयार की गई बैठक में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अनंत कुमार सोनी सहित संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे इस दौरान कार्यशाला के उद्देश्य, विषय-वस्तु, विशेषज्ञ वक्ताओं की सहभागिता, विभिन्न विश्वविद्यालयों की भूमिका तथा आयोजन की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि कार्यशाला को केवल एक अकादमिक कार्यक्रम तक सीमित न रखकर भारतीय ज्ञान परंपरा के व्यावहारिक, सांस्कृतिक और शोधपरक आयामों से भी जोड़ा जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और मूल्यपरक शिक्षण प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया वक्ताओं ने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जीवन मूल्यों और सतत विकास के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है इसलिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को भारतीय चिंतन, दर्शन और परंपरागत ज्ञान से परिचित कराना समय की आवश्यकता है बैठक में यह भी तय किया गया कि कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नीति-निर्माता शामिल होंगे, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयामों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं शोधार्थियों को अपने शोध, नवाचार और अनुभव साझा करने का अवसर भी मिलेगा।

नेवले के हमले में घायल ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू

तारारोड़ा गांव में घर के बाहर मिला, इलाज के बाद जंगल में छोड़ा

मीडिया ऑडीटर, इटारसी (निप्र)। इटारसी के करीब ग्राम तारारोड़ा में शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे एक मजदूर परिवार के घर के बाहर नेवले के हमले में गंभीर रूप से घायल इंडियन ब्लैक कोबरा मिला। सांप के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर बाहर देखा तो लगभग 4 फीट लंबा कोबरा घायल अवस्था में पड़ा था। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक शर्मा के निर्देश पर वन्य जीव अभिरक्षक अभिजीत यादव तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अत्यधिक सावधानी

बरतते हुए विषैले कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नेवले के हमले के कारण सांप के मुंह के पास गहरे घाव हो गए थे।

कोबरा को नेवले के 5 दांत लगे: अभिजीत यादव ने बताया कि नेवले के हमले में कोबरा सांप के मुंह में 4 से 5 दांत लग गए थे। पशु चिकित्सालय में उपचार के बाद कोबरा सांप को पुनर्वास के लिए इटारसी के तवा नगर के जंगल में छोड़ा गया है। रेस्क्यू के बाद घायल कोबरा को तत्काल उपचार के लिए पशु चिकित्सालय ले जाया गया। वहां पशु चिकित्सक ने उसका प्राथमिक उपचार किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपचार और उचित निगरानी के बाद सांप को वन क्षेत्र में उसके सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा।

'हर घर तिरंगा' अभियान 9 से 17 अगस्त तक

14 अगस्त को मनाया जायेगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। मध्यप्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त, 2026 तक संपूर्ण जन सहभागिता से चलाया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स को तत्संबंधी निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर्स से कहा गया है कि इस अभियान में जनसामान्य को विगत वर्षों की तरह उत्साह और देशभक्ति के साथ स्वाधीनता दिवस मनाने एवं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मानने के लिए सहभागिता सुनिश्चित करें। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत शासकीय कार्यक्रम/चर्चाएँ जैसे आयोजन किए जाएंगे।राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के साथ जोड़ा गया है।

'हर घर तिरंगा' अभियान 9 से 17 अगस्त 2026: प्रदेश में यह जन-आंदोलन 9 से 17 अगस्त 2026 की तिथियों में पूरी जनभागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा।

सभी जिलों में तिरंगा से प्रेरित कला, तिरंगा प्रदर्शनी का प्रदर्शन, तिरंगा रंगोली, तिरंगा बुनाई, तिरंगा पर प्रश्नोतरी, तिरंगे के लिए स्वयं सेवा, तिरंगा सजावट और प्रकाश व्यवस्था तथा सैन्य बलों के जवानों और पुलिसकर्मियों को 'पत्र लेखन' जैसे कार्यक्रम तथा तिरंगा संगीत कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जायेगा।

स्थानीय स्व-सहायता समूहो और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में खादी/पॉलिएस्टर के राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। अभियान में केंद्रित तिरंगा मेला, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा बाइक तिरंगा ई-बाइक/तिरंगा साइकिल रैली, उच्च जनभागीदारी के साथ तिरंगा यात्रा, तिरंगा ध्वजबिक्री और समुचित व्यवस्था, मानव श्रृंखला निर्माण, तिरंगा एंथम आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। डिजिटल सहभागिता अभियान में नागरिकों द्वारा तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने, एवं सोशल मीडिया हेण्डल पर अभियान का प्रचार-प्रसार के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

'वंदे मातरम' गान के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न: शासकीय कार्यक्रमों, शिक्षण संस्थानों तथा सार्वजनिक सभाओं में जहाँ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जा रहे हो, वहाँ 'वंदे मातरम' (राष्ट्रगीत) पहले गाया/बजाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान 'जन गण मन होगा।

राष्ट्रगीत गायन के दौरान उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक सावधान की मुद्रा में सम्मानपूर्वक खड़े रहेंगे।शासकीय कार्यालयों एवं महाविद्यालयों के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के निर्धारित छंदों का शुद्ध और गरिमापूर्ण वाचन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रत्यक्ष आयोजनों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का गायन और राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराना/प्रदर्शन करना दोनों शामिल किए जाएंगे।

इसी तरह, हर घर तिरंगा' की वेबसाइट (www.harghartiranga.com) पर नागरिकों द्वारा तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को अपलोड करने पर तस्वीर पर 'वंदे मातरम' अंकित होगा।

एनसीसी कैडेट्स ने चलाया स्वच्छ परिसर अभियान, दिया स्वच्छता का संदेश

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) इकाई द्वारा महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. बी. डी. अहीरवार के मार्गदर्शन में तथा एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. विनिता प्रजापति के संयोजन में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने पूरे महाविद्यालय परिसर की साफ-सफाई करते हुए प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर उनका उचित निस्तारण किया। कैडेट्स ने परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने का संकल्प लिया तथा स्वच्छता के महत्व के प्रति छात्राओं और

महाविद्यालय परिवार को जागरूक किया।

इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. बीडी अहीरवार ने कहा कि स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। उन्होंने कैडेट्स के अनुशासन , सेवा भावना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता विकसित करते हैं। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. विनीता प्रजापति ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी का उद्देश्य केवल सैन्य प्रशिक्षण देना ही नहीं, बल्कि समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है। उन्होंने सभी छात्राओं से अपने घर, महाविद्यालय एवं आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

स्वच्छता अभियान के दौरान कैडेट्स ने 'स्वच्छ परिसर - स्वस्थ परिसर ', 'स्वच्छता ही सेवा है' तथा 'स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत' जैसे प्रेरणादायक नारों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन सभी कैडेट्स द्वारा नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखने एवं समाज में स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के संकल्प के साथ हुआ। एनसीसी की ऐसी गतिविधियाँ विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा भावना एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मंदसौर में 62 किलो डोडाचूरा के साथ दंपती गिरफ्तार

पूछताछ में महिला तस्कर गिरोह का खुलासा, महिलाएं बच्चों संग करती थीं तस्करी

मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर जिले की अफजलपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 62 किलो 840 ग्राम डोडाचूरा के साथ एक दंपती को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कमालपुरा फंटा, ग्राम बिलात्री के पास की गई। उस समय दोनों आरोपी बस का इंतजार कर रहे थे।

एसपी विनोद कुमार मीना के निर्देश पर गुरुवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला और एक पुरुष अलग-अलग बैग में डोडाचूरा लेकर किसी बाहरी तस्कर को देने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरीश मालवीय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की।

पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम कादु उर्फ राधाबाई (48) पत्नी

आशाराम और पुरुष ने आशाराम उर्फ गंभीर (52) पिता चितामणि, निवासी प्रताप वार्ड, गांधी नगर, भोपाल बताया।

बरामद सामान की कीमत 1.25 लाख रुपए: तलाशी के दौरान विमल के थैले, लाल बैग, झोले और प्लास्टिक के कट्टे से कुल 62 किलो 840 ग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ। जब्त डोडाचूरा की अनुमानित कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 208/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 और 29 में मामला दर्ज किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

पूछताछ में महिला तस्कर गिरोह का खुलासा: थाना प्रभारी हरीश मालवीय ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि 3 से 8 महिलाओं का एक गिरोह डोडाचूरा की तस्करी करता है। शक से बचने के लिए ये महिलाएं अपने साथ छोटे या दूधमुंहे बच्चों को लेकर चलती थीं। गिरोह बसों के जरिए मादक पदार्थ गुजरात और राजस्थान तक पहुंचाता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क, सप्लायर और खरीदारों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े रहे हैं। उनके पुराने रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। जानकारी मिली है कि गिरफ्तार महिला करीब 20 साल पहले सीतामऊ थाना क्षेत्र में 7 किलो डोडाचूरा के मामले में भी पकड़ी जा चुकी है। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है।

'ऐसा लगा जैसे पहली बार टीम में चुना गया हूं'

टेस्ट टीम में वापसी पर इंग्लैंड के बल्लेबाज ने दिया बयान

लंदन,एजेंसी। : ऑस्ट्रेलिया के खराब एशेज दौरे के बाद टेस्ट टीम से बाहर किए गए इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में उनकी वापसी 'पहली बार चुने जाने' जैसा महसूस हो रही है। उनकी नजरें अगले साल घरेलू मैदान पर होने वाली एशेज सीरीज पर हैं और उनका मानना है कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ साबित करना है।

इंग्लैंड के लिए लंबे समय तक नंबर तीन पर खेलने वाले पोप को पाकिस्तान के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में वापस बुलाया गया है। यह तीन मैचों की घरेलू सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की 1-4 से हार के दौरान उनका प्रदर्शन खराब रहा था, उन्होंने 6 पारियों में 20 से ज्यादा की औसत से सिर्फ 125 रन बनाए थे। नंबर तीन की अपनी जगह जैकब बेथेल को गंवाने के बाद

अब वे एक अलग माहौल में वापसी कर रहे हैं। उनके टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और स्टीफन फ्लेमिंग ने ब्रेंडन मैकुलम से कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली है।

गुरुवार को यह पुष्टि हुई कि विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे और डैन लॉरेंस नंबर छह पर स्टोक्स की जगह लेंगे। पोप, जिन्होंने स्टोक्स की गैर-मौजूदगी में पांच टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की थी, अब 64 टेस्ट मैचों के अनुभव के साथ एक उपयोगी खिलाड़ी के तौर पर वापसी कर रहे हैं। उनसे ज्यादा टेस्ट मैच सिर्फ जो रूट ने खेले हैं।

टीम से बाहर किए जाने के बाद पोप ने सरे (Surrey) के लिए काउंटी क्रिकेट में कड़ी मेहनत की। उन्होंने 12 पारियों में 56.66 की औसत से 510 रन बनाए, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल थे। काउंटी में अपने प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए पोप ने कहा, 'काउंटी क्रिकेट में निराशाजनक बात यह थी कि मैं लगभग चार बार 70 के आसपास आउट हुआ (83, 69, 76, 73)। मेरे मन में यह ख्याल आता था कि 'क्या जब दोबारा चयन का समय आएगा तो मैं खुद को कोसूंगा कि मैंने उन पारियों को 150 या 170 रन में क्यों नहीं बदला?

पोप ने कहा कि पिछला डेढ़ साल टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए 'उतार-चढ़ाव भरा' (रोलरकोस्टर जैसा) रहा है। उन्होंने कहा, 'कल का बुलावा ऐसा लगा जैसे पहली बार टीम में चुना गया हूं। मुझे इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन पक्का भरोसा नहीं था। हो सकता है कि टीम लिस्ट में मेरा नाम सबसे पहले न हो, लेकिन यह उस मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ने जैसा है जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ।'

पोप ने कहा, 'मैंने दुनिया भर में हर जगह खेला है। मुझे अच्छा प्रदर्शन करने का अनुभव है, और मैं जानता हूं कि इन हालात में अच्छा खेलने के लिए मुझे अब क्या करने की जरूरत है। मुझे बस उस सीरीज का इंतजार था जिसमें लगातार शतक पर शतक लगाए जा सकें। जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं बस यह पक्का करना चाहता हूं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं।'

आर प्रज्ञानानंद ने जीता सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब

सेंट लुइस,एजेंसी। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने एक राउंड बाकी रहते हुए ही ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम किया। प्रज्ञानानंद और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के बीच आखिरी मुकाबले का अंत ड्रॉ पर होने के साथ ही भारतीय ग्रैंडमास्टर का खिताब पक्का हो गया। 20 साल के भारतीय खिलाड़ी ने कुल 35 में से 23 प्वाइंट हासिल करके चैंपियनशिप को अपने नाम किया। शानदार टूर्नामेंट के बाद सिंदारोव ने 22 प्वाइंट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि वेस्ली सो 20.5 प्वाइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। लेवोन अरोनियन 19 प्वाइंट के साथ चौथे स्थान पर रहे, और फैबियानो कारुआना, लीनियर डोमिंग्वेज और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट 17 प्वाइंट के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहे। प्रज्ञानानंद को बिना किसी प्लेऑफ के सीधे जीत हासिल करने पर 50,000 अमेरिकी डॉलर और 13 ग्रैंड चेस टूर प्वाइंट मिले। इस नतीजे से प्रज्ञानानंद सिंकफील्ड कप से पहले ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि फैबियानो अभी भी ओवरऑल ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। प्रज्ञानानंद ने पांच दिन के इस इवेंट में शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखी। सिंदारोव ने आखिरी दौर में कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए और 1.5 प्वाइंट के अंतर से उपविजेता रहे। जून में, प्रज्ञानानंद प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच चुके हैं। सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में 31 जुलाई से 7 अगस्त तक सेंट लुइस चेस क्लब में दस बेहतरीन ग्रैंडमास्टर शामिल हुए। पांच दिनों के खेल में, खिलाड़ियों ने 9 रैपिड राउंड और 18 ब्लिट्ज राउंड खेले। इस दौरान कुल मिलाकर 135 गेम हुए, जिनमें सिंकफील्ड कप और जीसीटी ग्रैंड फाइनल से पहले महत्वपूर्ण टूर प्वाइंट दांव पर थे। इस टूर्नामेंट में दो तेज गति वाले फॉर्मेट शामिल रहे। 9-राउंड का सिंगल राउंड-रॉबिन रैपिड टूर्नामेंट (जो 25 मिनट के टाइम कंट्रोल और पहली चाल से ही 10-सेकंड के इंक्रीमेंट के साथ खेला जाता है) और 18-राउंड का डबल राउंड-रॉबिन ब्लिट्ज टूर्नामेंट (जो 5 मिनट के टाइम कंट्रोल और पहली चाल से ही 2-सेकंड के इंक्रीमेंट के साथ खेला जाता है)। रैपिड में जीत पर 2 पॉइंट और ड्रॉ पर 1 प्वाइंट मिलता है, जबकि ब्लिट्ज में जीत पर 1 प्वाइंट और ड्रॉ पर 0.5 प्वाइंट मिलता है।

बचपन में उठाए लकड़ियों के गठ्ठर, ट्रक ड्राइवरों से लेनी पड़ी लिफ्ट

कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की हैट्रिक लगातार रचा इतिहास

नई दिल्ली ,एजेंसी। कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भारत के महिला वेटफिल्टर मीराबाई चानू शायद इस बात को बखूबी जानती और मानती भी हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में तीन गोल्ड मेडल जीतने वालीं दुनिया की इकलौती वेटलिफ्टर मीराबाई के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं रही, हालांकि उन्होंने हर कदम और हर मोड़ पर संघर्ष का दामन थामे रखा और हर विपरीत परिस्थिति से निकलकर विश्वभर में अपने खेल के दम पर अलग पहचान बनाई। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त, 1994 को मणिपुर के इंफाल के पास स्थित नोंगपोक काकचिंग में हुआ। मीराबाई एक साधारण परिवार से आती थीं, तो आर्थिक तंगी और शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा रहा, हालांकि भारतीय महिला वेटलिफ्टर के अंदर बचपन से ही असाधारण शारीरिक क्षमता थी। वह लकड़ियों के भारी गठ्ठर उठाया करती थीं। वह इन गठ्ठर को उठाकर पहाड़ियों पर भी चढ़ा करती थीं। मीराबाई के परिवार का किसी भी खेल से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था, हालांकि बेटी की क्षमता को देखते हुए माता-पिता ने हमेशा मीराबाई को सपोर्ट किया। मीराबाई की दिलचस्पी पहले तीरंदाजी में थी, लेकिन इंफाल के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में वेटलिफ्टिंग की ट्रेनिंग को देखकर इस खेल के प्रति मीराबाई की दिलचस्पी बढ़ी। उन्होंने जल्द ही इस खेल में अपना करियर बनाने की ठान ली। घरेलू प्रतियोगिताओं में मीराबाई की प्रतिभा का हर कोई कायल हो गया। मीराबाई ने साल 2008 में मणिपुर स्पोर्ट्स अकादमी में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें अकादमी तक पहुंचने के लिए रास्ते में बालू और पत्थर लेकर जाने वाले ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट मांगनी पड़ती थी। नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मीराबाई चानू ने साल 2014 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना डेब्यू किया। मीराबाई का डेब्यू शानदार रहा और उन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, हालांकि यह उनके शानदार करियर की महज शुरुआत मात्र थी। साल 2017 में विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहीं। वह दो दशकों में यह गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बनीं। इसके बाद साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर का जलवा देखने को मिला और उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। वह ओलंपिक में सिल्वर जीतने वालीं पहली भारतीय वेटलिफ्टर बनीं। 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहीं और उन्होंने लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

रवींद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में शानदार रिकॉर्ड, आंकड़ों पर डालें नजर

कोलंबो (श्रीलंका),एजेंसी। : श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान टीम इंडिया और उसके फैन्स महान ऑलराउंडरों में से एक, रवींद्र जडेजा को 'लंकन लायंस' (श्रीलंकाई टीम) के खिलाफ खेलते हुए देखेंगे, एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ खेलना उन्हें पसंद है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच न खेलने के बाद जडेजा श्रीलंका की स्पिन-फ्रेंडली (स्पिनरों के लिए मददगार) परिस्थितियों में वापसी करेंगे। उन्होंने पिछली बार सफेद जर्सी (टेस्ट मैच) में तब खेला था जब भारत को पिछले साल घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के हाथों बुरी तरह हार (व्हाइटवॉश) का सामना करना पड़ा था।

● रविंद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट रिकॉर्ड

जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 7 टेस्ट मैचों में 9 पारियों में 65.20 की औसत से 326 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रहा है। उन्होंने 23.72 की औसत से 33 विकेट भी लिए हैं, जिसमें दो बार एक पारी में 5 विकेट लेना और 5/41 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है। कुल मिलाकर श्रीलंका के खिलाफ 48 इंटरनेशनल मैचों में जडेजा ने 34 पारियों में 46.52 की औसत से 791 रन बनाए हैं (एक शतक और दो अर्धशतक के साथ) और 31.87 की औसत से 66 विकेट भी लिए हैं (दो बार एक पारी में पांच विकेट लेने के साथ)।

- **कुल टेस्ट - 7**
- **इनिंग्स - 9**
- **औसत - 65.20 की**
- **रन - 326 रन**
- **शतक - एक**
- **अर्धशतक - एक**
- **सर्वश्रेष्ठ स्कोर - 175**
- **कुल विकेट - 33**
- **पारी में 5 विकेट - दो बार**
- **सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन - 5/41**

जडेजा ने 89 टेस्ट मैचों में गेंदबाजी करते हुए 25.11 की औसत से 348 विकेट लिए हैं। उनके नाम 17 बार चार विकेट, 15 बार पांच विकेट और तीन बार दस विकेट लेने का कारनामा दर्ज है, और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/42 रहा है। उन्होंने 133 पारियों में 38.27 की औसत से 4,095 रन भी बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और आठ अर्धशतक शामिल हैं। हर गुजरते साल के साथ, बल्ले और गेंद के साथ जडेजा की भरोसेमंदता और बढ़ी है, जिससे वह आधुनिक युग के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक बन गए हैं।

शुभमन गिल को लगी चोट

श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म-अप टेस्ट के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे

कोलंबो,एजेंसी। : भारतीय कप्तान शुभमन गिल श्रीलंका क्रिकेट (SLC) XI के खिलाफ तीन दिन के वॉर्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे। BCCI ने शुक्रवार को बताया कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी दाहिने हाथ की रिंग फिंगर (अनामिका) में चोट लग गई थी। गिल की गैर-मौजूदगी में SLC XI के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद उप-कप्तान केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे हैं। टॉस के ठीक बाद BCCI ने एक बयान में कहा, 'गुरुवार को भारत की प्रैक्टिस के दौरान कप्तान शुभमन गिल की दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में चोट लग गई थी। एहतियात के तौर पर वह SLC XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे। BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है।' चार दिन से घटाकर तीन दिन का किया गया यह वॉर्म-अप मैच 15 अगस्त से गॉल में श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारत के लिए तैयारी का एक अहम मौका है। भारत ने आखिरी बार जून में टेस्ट क्रिकेट खेला था, इसलिए यह मैच उन्हें श्रीलंकाई हालात (जो मुख्य रूप से स्पिन-फ्रेंडली होते हैं) के अनुकूल ढलने का एक महत्वपूर्ण अवसर देता है। यह मैच शुभदीप घोष के फील्डिंग कोच के तौर पर कार्यकाल की शुरुआत भी है, क्योंकिBCCI ने उनसे पहले इस पद पर रहे टी. दिलीप और असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट का कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था।

जहां बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में मामूली चोट से धीरे-धीरे उबर रहे हैं, वहीं टीम घुटने की चोट के कारण प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना खेल रही है। बुमराह की गैर-मौजूदगी के कारण जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया गया है ।

जब हेजलवुड ने पुजारा को गेंदबाजी करने से मना कर दिया था,

भारत के पूर्व बल्लेबाज ने सुनाया किस्सा

नई दिल्ली,एजेंसी। : भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ अपने समय के दौरान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के साथ हुई एक घटना का जिक्र किया जब हेजलवुड ने उन्हें नेट्स में गेंदबाजी करने से मना कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में 2018/19 और 2020/21 में भारत की यादगार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज जीत के दौरान हेजलवुड का सामना करते हुए घंटों बिताने के बाद पुजारा ने ढ्ढक्कमें ष्टस्य्य के साथ अपने समय के दौरान हेजलवुड के साथ हुई मज़ेदार बातचीत को साझा किया।

पुजारा ने जियो हॉटस्टार की सीरीज 'चीकी सिंगल्स' (Cheeky Singles) में कहा, '2018 और 2021 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान मैंने जोश हेजलवुड के खिलाफ काफी खेला। फिर मुझे ष्टस्य्य ने चुन लिया। जब मैं पहली बार नेट्स में बल्लेबाजी करने गया, तो हेजलवुड ने मुझे गेंदबाजी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, 'मैं उसे गेंदबाजी नहीं करूंगा।' हालाँकि वह मेरे टीम के साथी थे, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मजाक में कहा कि IPL से पहले के कुछ महीनों में उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गेंदबाजी की थी, इसलिए वह मुझे दोबारा गेंदबाजी नहीं करने वाले थे। वह मजाक कर रहे थे, लेकिन असल में उन्होंने मुझे गेंदबाजी नहीं की।' अपने शुरुआती IPL करियर को याद करते हुए पुजारा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक और अभिनेता-निर्माता शाहरुख खान से मिलने पर एक 'फैनबॉय मोमेंट' का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी की मौजूदगी से ज्यादा खिलाड़ी की प्राथमिकता टीम कल्चर और क्रिकेट के विकास पर होती है।

उन्होंने कहा, 'मैंने ऋयक्रके साथ शुरुआत की थी। शाहरुख खान वहां के मालिक थे। जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो निश्चित रूप से मुझे वह 'फैनबॉय मोमेंट' महसूस हुआ। लेकिन जब आप क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, तो आप यह नहीं सोच सकते कि 'सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान मालिक हैं, मैं यहां रहना चाहता हूं।' आप वहां इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि फ्रैंचाइजी ऐसा माहौल बनाती है, जहां दिग्गज खिलाड़ियों से सीखने, उनके साथ खेलने और अपने क्रिकेट को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। यही मायने रखता है।'

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा एक्शन

क्रिकेटर पर लगाया दो साल का बैन और 10 लाख जुर्माना

लाहौर,एजेंसी। : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 6 अगस्त 2026 को घरेलू क्रिकेटर हमजा नजर को सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियों से 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया और उन पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई PCB के जरिए वीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान नजर द्वारा दी गई जानकारी की औपचारिक अनुशासनात्मक जांच के बाद की गई। बोर्ड की आधिकारिक जानकारी के अनुसार जांच में यह पाया गया कि उन्होंने पूरी और सही जानकारी नहीं दी, गुमराह करने वाली जानकारी दी और उस प्रक्रिया के दौरान जरूरी तथ्यों को छिपाया था।

मामले की जांच के लिए PCB ने तीन सदस्यों का एक पैनल बनाया। पैनल ने सभी उपलब्ध जानकारी की समीक्षा की, नजर का पक्ष सुना और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें भेजने से पहले उन्हें हर मामले पर अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। इसके बाद PCB ने उन सिफारिशों के आधार पर अंतिम सजा तय की। तीन सदस्यीय पैनल का मुख्य निष्कर्ष यह था कि PCB के जरिए वीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान नजर ने पारदर्शिता नहीं बरती थी। समिति ने तीन खास कमियां पाईं, उन्होंने पूरी और सही जानकारी नहीं दी, उन्होंने गुमराह करने वाली जानकारी दी और उन्होंने जरूरी तथ्यों को छिपाया।

PCB की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में पुष्टि की गई कि समिति ने सभी उपलब्ध सबूतों की समीक्षा करने और नजर का पक्ष सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपीं। बोर्ड ने खेलने पर बैन और जुर्माना लगाने का अपना फैसला सीधे उसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया।

नजर एक राइट-आर्म ऑफ-ब्रेक बॉलर हैं जो पाकिस्तान के घरेलू सर्किट में खेलते हैं। PCB की आधिकारिक जानकारी में उस खास देश की पुष्टि नहीं की गई है जिसके लिए वीजा आवेदन किया गया था, इसलिए इस रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया गया है।

● बैन का क्या मतलब है?

इस सस्पेंशन के कारण नजर पूरे दो साल तक PCB द्वारा मंजूर किसी भी क्रिकेट गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते। इसमें घरेलू प्रतियोगिताएं और बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शामिल है, जिससे बैन खत्म होने तक वे पाकिस्तान में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे। खेलने पर बैन के साथ-साथ 10 लाख PKR का जुर्माना एक अलग सजा है, जो यह दिखाता है कि PCB ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया है। यह दोहरी सजा बोर्ड के इस रुख को दिखाती है कि किसी आधिकारिक प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता की कमी होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ की दो खिलाड़ी भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम में, चीन में होने वाले एशिया कप में दिखाएंगी दम

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के लिए खेल जगत से आज एक और बड़ी खुशखबरी आई है। बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की दो खिलाड़ियों गीता यादव और मधु सिदार का चयन भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है। ये दोनों चीन के मोकी में आगामी 30 अगस्त से 13 सितम्बर तक होने वाले जूनियर एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा और दम दिखाएंगी। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने गीता यादव और मधु सिदार से वीडियो-कॉल पर बात कर भारतीय टीम में चयन पर बधाई दी। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को जूनियर एशिया कप हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामना देते हुए उनकी तैयारियों की भी जानकारी ली। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती तनुजा सलाम ने भी दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम में चयनित ये दोनों ही खिलाड़ी प्रदेश की पहली आवासीय खेल अकादमी में वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री राकेश टोप्पो एवं मुख्य प्रशिक्षक श्री अजीत लकड़ा से हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

ऐसा रहा है टीम इंडिया तक दोनों खिलाड़ियों का सफर

मधु सिदार : मधु सिदार हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले जशपुर जिले के कांसाबेल के छोटे से गांव पोंगरो की रहने वाली है। उनके माता-पिता कृषक हैं। वह सब-जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024-25, स्कूल नेशनल 2024-25 तथा हरियाणा में सब-जूनियर इंटर जोन चैम्पियनशिप-2025 में भागीदारी कर चुकी हैं। उनकी टीम ने आंध्रप्रदेश में 1 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक आयोजित हॉकी इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप में चतुर्थ स्थान हासिल किया था। मधु इस साल मार्च-अप्रैल में छत्तीसगढ़ में आयोजित देश के पहले खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स में भी खेल चुकी है। वह अप्रैल-2026 से बेंगलुरू में भारतीय टीम के साथ प्रशिक्षण ले रही हैं।

गीता यादव: कबीरधाम जिले के बोड़ला की गीता यादव ने हॉकी का प्रारंभिक प्रशिक्षण कोच श्री शिवा चौहान से प्राप्त किया है। गीता के अंतरराष्ट्रीय करियर का सफर वर्ष-2024 में प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने 12 नवम्बर से 21 नवम्बर 2024 तक नीदरलैण्ड और बेल्जियम टूर में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद 15 मई से 2 जून 2025 तक अर्जेंटीना टूर और 5 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड टूर में भी वह भारतीय टीम का हिस्सा थीं।

होजाई जिला समिति (असम) के उपसभापति श्री रमाकांत गौड़ ने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी से की आत्मीय मुलाकात

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। होजाई जिला समिति (असम) के उपसभापति श्री रमाकांत गौड़ ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी से आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों के बीच समसामयिक विषयों, सुशासन, जनकल्याण तथा विभिन्न राज्यों के विकास संबंधी अनुभवों पर सार्थक चर्चा हुई। श्री गौड़ ने वित्त मंत्री श्री चौधरी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने श्री रमाकांत गौड़ का आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद से बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है, जो जनहित और विकास को नई दिशा प्रदान करता है।

सेवा सेतु बना आमजन का भरोसेमंद डिजिटल साथी एक सप्ताह में मिला जाति प्रमाण पत्र

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सरकारी सेवाओं को आम नागरिक तक सरल, त्वरित और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की दिशा में सेवा सेतु प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम मोहड़ निवासी यादव राम चंद्राकर इसके उदाहरण हैं। उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और महज एक सप्ताह के भीतर उनका प्रमाण पत्र जारी हो गया। इससे न केवल उनका समय बचा, बल्कि कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने और अनावश्यक खर्च से भी राहत मिली। यादव राम चंद्राकर बताते हैं कि पहले छोटे-छोटे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आवेदन की स्थिति जानने में भी काफी समय और मेहनत लगती थी। लेकिन सेवा सेतु ने पूरी प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बना दिया है। अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्यवस्था ग्रामीण नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है। उल्लेखनीय है कि पहले प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल 86 शासकीय सेवाएं उपलब्ध थीं। बदलती जरूरतों को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया गया, जिसमें अब 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध हैं। इससे शासन की सेवाएं अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध हुई हैं। सेवा सेतु डिजिटल सुशासन को मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों के समय, श्रम और धन की बचत कर शासन और जनता के बीच विश्वास का नया सेतु भी बन रहा है।

रक्षाबंधन पर डाक विभाग की विशेष पहल: 10 रुपये में मिलेगा राखी लिफाफा, राखी डाक के लिए लगाई गईं पीली विशेष पत्र पेटियां

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने बहनों की राखियां समय पर भाइयों तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। विभाग द्वारा तैयार विशेष राखी लिफाफा छत्तीसगढ़ के सभी प्रधान डाकघरों एवं उपडाकघरों में मात्र 10 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इस लिफाफे के माध्यम से राखी को स्पीड पोस्ट अथवा साधारण डाक से आसानी से भेजा जा सकता है। अधीक्षक डाकघर, रायगढ़ संभाग ने बताया कि राखी डाक के त्वरित निपटान के लिए 1 से 29 अगस्त 2026 तक विशेष पीले रंग की पत्र पेटियां स्थापित की गई हैं। रायगढ़ में ये विशेष पत्र पेटियां प्रधान डाकघर रायगढ़, चक्रधरनगर उपडाकघर, सदर बाजार उपडाकघर तथा कमला नेहरू पार्क में लगाई गई हैं। विभाग ने यह भी आग्रह किया है कि लिफाफे पर प्राप्तकर्ता का पूरा पता एवं पिनकोड स्पष्ट और साफ अक्षरों में अंकित करें, जिससे डाक वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री करेंगे 'कोशल फेब' ब्रांड और 'बिलासा' लोगो का शुभारंभ बुनकरों को मिलेगी करोड़ों की सौगात

राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर भव्य राज्य स्तरीय समारोह आज

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकर समुदाय को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक कला को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों व विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों में छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार, शिल्पियों का सम्मान और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनियां मुख्य आकर्षण होंगी। हाथकरघा उद्योग के संवर्धन, स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने और बुनकरों के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में

ग्रामोद्योग एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव उपस्थित रहेंगे। 'कोशल फेब' ब्रांड और 'बिलासा' लोगो का होगा लोकार्पण समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ की कई नई पहलों की शुरुआत की जाएगी। हाथकरघा संघ के नए प्रीमियम ब्रांड 'कोशल फेब' का भव्य शुभारंभ किया जाएगा और 'बिलासा' लोगो का अनावरण किया जाएगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का प्रस्तुतीकरण व शुभारंभ के साथ पुरस्कृत बुनकरों की डायरेक्टरी तथा टाई-डाई व बांधनी रंगाई पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। बुनकरों व मेधावी विद्यार्थियों को करोड़ों रुपये की सहायता और सम्मान राशि कार्यक्रम में ग्रामोद्योग विभाग के विभिन्न घटकों द्वारा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत राशि एवं सामग्री वितरित की जाएगी। कक्षा 10वीं व 12वीं के 935 मेधावी विद्यार्थियों को 81.83 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा 17 वरिष्ठ बुनकरों को 1.87 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। स्व. बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार और राजराजेश्वरी करुणा माता बुनकर पुरस्कार के तहत चयनित 8 बुनकरों को 1-1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। 49 बुनकरों को आवास निर्माण के लिए 122.50 लाख रुपये, 5 बुनकर समितियों को भवन निर्माण हेतु 75 लाख रुपये और 85 बुनकरों को उन्नत उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 14.92 लाख रुपये की स्वीकृति दी जाएगी। रेशम कृषकों को 15 लाख रुपये की किश्त, माटीशिल्पियों को विद्युत चाक, हस्तशिल्पियों को टूल-किट और जशपुर के ग्राम गोरिया में ग्लेजिंग यूनिट हेतु 2.86 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। साथ ही बुनकर नेत्र परीक्षण अभियान के तहत पात्र बुनकरों को चश्मे बांटे जाएंगे। फैशन शो में रैंप पर दिखेगा बस्तर की प्रतिभाओं और कोसा सिल्क का जलवा समारोह का मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित एक विशेष फैशन शो होगा। इसमें कोसा सिल्क और हैंडवुवन कॉटन के परिधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस फैशन शो की खासियत बस्तर की युवा प्रतिभागियों की सहभागिता होगी, जो पेशेवर मॉडलों और मिस इंडिया अर्थ 2026 अनुष्का सोने के साथ रैंप पर अपनी चमक बिखेरेंगी। इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश भर से बुनकर, हस्तशिल्पी, रेशम कृषक, माटीशिल्पी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे।

अंतिम गांव तक पहुंची स्वास्थ्य सुविधा, जंगमपाल में बदली जिंदगी की तस्वीर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। दूरस्थ गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगा है। दंतेवाडा कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना, नए स्वास्थ्य भवनों का निर्माण, जिला अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार और मेडिकल कॉलेज की स्थापना जैसे कदमों से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से अधिक सशक्त हुई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तीन महीने में 23 सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराया गया गांव में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कटेकल्याण विकासखंड के अंतर्गत स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर जंगमपाल इसका प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है। यह जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित जिले के

अंतिम उप स्वास्थ्य केंद्रों में से एक है। पहले यहां के लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल या सुकमा जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्राथमिक उपचार सहित 12 प्रकार की जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क लैब जांच, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, टीकाकरण और प्राथमिक उपचार सहित 12 प्रकार की जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। सबसे बड़ा बदलाव मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में आया है। अब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही उनकी नियमित जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान, लगातार निगरानी और सुरक्षित संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध है।

23 गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराया गया: इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि पिछले तीन महीनों में जंगमपाल आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 23 गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराया गया है। यह उपलब्धि ग्रामीणों के बढ़ते विश्वास और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता को दर्शाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके ने बताया कि जंगमपाल आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्रामीणों को नियमित रूप से प्राथमिक उपचार, गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य परामर्श और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

मजबूत होती स्वास्थ्य व्यवस्था की एक प्रेरणादायक मिसाल: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जंगमपाल की सफलता जिले की मजबूत होती स्वास्थ्य व्यवस्था की एक प्रेरणादायक मिसाल है। सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से जंगमपाल जैसे दूरस्थ गांवों में भी अब सुरक्षित मातृत्व और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का नया भरोसा बना है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण मिलने पर रेणुका गोस्वामी को दी बधाई

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। धमतरी जिले के ग्राम नवागांव की बेटी रेणुका गोस्वामी को आगामी 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रण मिलने पर उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल रेणुका गोस्वामी की मेहनत और प्रतिभा का गौरव है, बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों, ग्रामीण युवाओं और कौशल विकास की सफलता का भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि रेणुका गोस्वामी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा दी और आज वे अपने परिश्रम एवं प्रतिभा के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उनका राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है। सुश्री रेणुका गोस्वामी धमतरी जिले के ग्राम नवागांव की निवासी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया और कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। निरंतर मेहनत, कौशल और लगन के बल पर उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करते हुए अपनी पहचान बनाई। वर्तमान में वे रायपुर के एक प्राइवेट फर्म में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं तथा लगभग 40 हजार रुपए प्रतिमाह का वेतन प्राप्त कर रही हैं। उनकी सफलता से परिवार की आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार आया है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। रेणुका गोस्वामी जैसी सफल युवतियां इस बात का प्रमाण हैं कि सही मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प के बल पर ग्रामीण अंचल के युवा भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति भवन में रेणुका गोस्वामी की उपस्थिति प्रदेश की बेटियों और युवाओं का उत्साह बढ़ाएगी तथा अन्य युवाओं को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी।

विश्व स्तनपान सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सफल आयोजन, छत्तीसगढ़ के प्रथम 'मातृ दूध कोष

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। विश्व स्तनपान सप्ताह (01-07 अगस्त 2026) के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आज रायपुर स्थित नया सभागृह, अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम काआयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में स्तनपान के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, शिशुओं के समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण 'माता यशोदा सम्मान' रहा, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 10 माताओं को सम्मानित किया गया। इन माताओं ने अपने मातृ दुग्ध का दान कर ऐसे नवजात शिशुओं को जीवनदायी सहयोग प्रदान किया, जिन्हें अपनी माताओं का दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। सम्मान समारोह के माध्यम से मातृ दुग्ध दान को एक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने का संदेश दिया गया तथा मातृत्व, संवेदनशीलता और मानवता की इस अनूठी मिसाल को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री अमित कटारिया, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्री संजीव झा, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा, कुलपति आयुष विश्वविद्यालय, डा. विवेक चौधरी डीन पंडित जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज ने भाग लिए 7 कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा ह्यूमन मिल्क बैंक स्टॉल के अवलोकन से हुआ। इसके पश्चात अतिथियों के मंचासीन होने के बाद दीप प्रज्ज्वलन एवं वंदे मातरम् के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम, सुरक्षित एवं संपूर्ण आहार है तथा स्वस्थ एवं सशक्त समाज की आधारशिला है। उन्होंने मितानिन कार्यक्रम के 25 वर्षों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मितानिन बहनों ने दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने माता शबरी के सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार माता शबरी ने बिना किसी स्वार्थ के दीन दुखियों, जरूरतमंदों व प्रभु श्रीराम की सेवा की, उसी प्रकार प्रदेश की 72 हजार मितानिन बहनें समाज के गरीब, जरूरतमंद, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं और वे आज की वास्तविक 'शबरी' हैं। उन्होंने प्रदेश के प्रथम 'मातृ दूध कोष (Human Milk Bank) की स्थापना को नवजात शिशुओं के लिए एक ऐतिहासिक एवं जीवनदायी पहल बताते हुए कहा कि इससे अनेक शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध उपलब्ध हो सकेगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक प्रभावशाली उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक भी 'माँ का दूध' ही माना जाता है और अक्सर चुनौती देते समय लोग कहते हैं, 'माँ का दूध पिया है तो आ जा '। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि माँ के दूध की शक्ति, संस्कार और जीवनदायी महत्व का प्रतीक है। अंत में उन्होंने सभी से संकल्प लेने का आह्वान किया कि प्रदेश का कोई भी नवजात माँ के अमूल्य दूध से वंचित न रहे तथा स्तनपान को जन-आंदोलन बनाया जाए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि सीबीजी इकोसिस्टम के विकास के लिए भारत सरकार ने स्वीकृत किए 50 करोड़ रुपये

स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय में वृद्धि और हरित अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकोसिस्टम के विकास के लिए किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी प्रयासों की सराहना करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (SASCI) 2026-27 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए

निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति राज्य के कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी। इससे कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित होगा, किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा तथा पराली और अन्य जैव अवशेषों के बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को जैव ईंधन एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। सीबीजी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश, रोजगार, किसानों की आय, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। राज्य सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 को 8 जून 2026 को अधिसूचित किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, पैडी स्ट्रॉ तथा अन्य बायोमास का वैज्ञानिक रूपांतरण कर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्वच्छ गैसीय ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। इससे किसानों को बायोमास की आपूर्ति से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, वहीं संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सीबीजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्यप्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी
आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा